सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 22, नई दिल्ली | शुक्रवार, 07 अप्रैल 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों पर निर्भर करता है, वहीं अच्छे विचार व्यक्ति को विकास के पथ पर अग्रसर करते हैं।

उम्र पूरी कर चुके वाहनों का एक माह में करना होगा 'काम तमाम', ये हैं स्क्रैपिंग के नए नियम

संजय बाटला

ऐसे वाहनों की पूरी स्क्रैपिंग एक माह में पूरी करनी होगी। 15 दिन में डी पल्युशन जबकि अगले 15 दिनों में डिस्मेंटल का काम किया जाएगा। बेकार गाड़ियां काफी बड़ी हो सकती हैं इसलिए इनकी हेंडलिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

नई दिल्ली। उम्र पूरी कर चुके वाहनों यानी ईएलवी (एंड आफ लाइफ वीकल) की स्क्रैपिंग के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण अनुकूल नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत ऐसे वाहनों की पूरी स्क्रैपिंग एक माह में पूरी करनी होगी। 15 दिन में डी पल्युशन जबकि अगले 15 दिनों में डिस्मेंटल का काम किया जाएगा।

सीपीसीबी ने जारी की नई गाइडलाइंस

सीपीसीबी के अनुसार आटोमोटिव सेक्टर के साथ साथ ऐसी गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है जो अपनी समय सीमा पूरी कर चुकी हैं। लेकिन इन गाड़ियों की स्क्रैपिंग भी समस्या बढ़ा रही है। इसलिए ऐसी गाड़ियों के लिए संग्रहण, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, इससे निकलने वाले कचरे आदि के लिए नियम तय करना जरूरी है।

ऐसी गाड़ियों में कई खतरनाक पदार्थ भी होते हैं, जिसमें खराब तेल, लूबरिकेंट, खराब बैट्री, लैंप, अन्य इलेक्ट्रानिक चीजें के साथ एयर बैग आदि शामिल हैं। यह सामान भी एक चिंता का विषय है। पहला यह स्क्रैपिंग साइट पर काम करने वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं और दूसरा इनका सही निस्तारण न होने पर यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह हैं।

इस समय ज्यादातर स्क्रैप यार्ड का मैनेजमेंट सेमी फार्मल सेक्टर में हो रहा है। इसकी वजह से इसमें काफी कमियां हैं। बेकार हो चुकी इन गाड़ियों में कई धातुएं और चीजें ऐसी हैं जिनको अगर सही तरीके से रिसाइकल किया जाए तो यह इकोनामी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। सीपीसीबी के अनुसार अभी भी देश में 70 प्रतिशत कटने वाली गाड़ियां सीधे दोबारा इस्तेमाल होती है या दूसरे निर्माता को बेच दी जाती हैं।

स्क्रैपिंग की प्रक्रिया:-

सबसे पहले बेकार हो चुकी गाड़ियों का डी पल्युशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में गाड़ियों के सभी खतरनाक उपकरण जैसे बैट्री, फ्यूल, फ्लूयड, एयर बेग, केटालिस्ट, सभी तरह की धातुओं वाले उपकरणों को अलग किया जाता है। इसके बाद गाड़ी को डिस्मेंटल किया जाता है। इस प्रक्रिया में गाड़ी के हिस्सों को अलग करना और रिसाइकल वाले हिस्से को कलेक्ट करना शामिल रहता है। इसमें इस्तेमाल और दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीजों को बेच दिया जाता है। इसमें हल्क, मोटर पार्ट्स, बैट्री, ईंधन आदि शामिल होता है। रिसाइकल होने वाली चीजों जैसे कारपेट, टायर या अन्य धातुओं को संबंधित सेंटरों पर भिजवाया जाता है।

गाड़ी के डी पल्युशन और डिस्मेंटलिंग के समय जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसका शोधन करना जरूरी होता है। इसके बाद अन्य बचे हिस्सों को आटोमेटिव श्रेडर मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकडे.कर दिए जाते हैं।

> सीपीसीबी के अनुसार आटोमोटिव सेक्टर के साथ साथ ऐसी गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है जो अपनी समय सीमा पूरी कर चुकी हैं। लेकिन इन गाड़ियों की स्क्रैपिंग भी समस्या बढ़ा रही है।

स्क्रैपिंग के नए नियम:-

- नए व्हीकल सर्विस सेंटर को अपग्रेड कर कलेक्शन सेंटर बनाया जा सकता है। गाड़ियों को रिसाइकल करने वाले लोग गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं। इस तरह के कलेक्शन सेंटर 50 किलोमीटर के दायरे को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। यह कलेक्शन सेंटर सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन सेंटर से जुडे.हों। यदि इन कनेक्शन सेंटर में डी पल्युशन और डिस्मेंटलिंग का काम करना है तो वह मोटर व्हीकल रूल 2021 के अनुरूप करना होगा। बेकार गाड़ियां काफी बड़ी हो सकती हैं इसलिए इनकी हेंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- गाड़ियों का डी पल्युशन करने के बाद उन्हें पंद्रह दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। साथ ही गाड़ियों से किसी तरह का फ्लूयड लीक नहीं होना चाहिए। गाड़ियां ऐसी जगह में खड़ी की जाएं जो पूरी तरह सूखी हों। गाड़ियां कच्ची जगह की बजाय पक्की जगह पर स्टोर की जाएंगी। ऐसी गाड़ियों को बाढ़ संभावित एरिया, झीलों, तलाबों के पास नहीं रखा जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति के आसपास भी इस तरह की गाड़ियों को नहीं रखा जा सकता। गाड़ियों को एक लाइन में पार्क किया जाएगा और हर लाइन के बीच में आने जाने की जगह रहेगी।
- गाड़ियों को डी पल्युशन करने की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित हो। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले बैट्री को डिस्कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद ईंधन, आयल फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक फ्यूल, पावर स्टीयरिंग कैप्स आदि को निकाला जाएगा। इसके बाद पहिए और टायर, व्हील बेलेंसिंग, वेट कैप्स आदि को निकाला जाएगा। इसके बाद गाड़ी को तय जगह पर रखकर उससे अतिरिक्त फ्लूयड और गैस निकाली जाएगी। स्क्रैप के लिए आने वाली गाड़ियों की डी पल्युशन प्रक्रिया पंद्रह दिन में पूरी होनी चाहिए।
- गाड़ियों से निकले वाले तरल पदार्थ को जरूरत के अनुसार रिसाइकल प्लांट या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा।

बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक एक पैसेंजर कार में 70 प्रतिशत स्टील, सात से आठ प्रतिशत अल्युमिनियम होता है। बाकी में 20 से 25 प्रतिशत प्लास्टिक, रबड़, ग्लास आदि होते हैं। एक टन स्टील को रिसाइकल करने से 1,134 किलो लोहा, 635 किलो कोयला और 54.4 किलो लाइमस्टोन की बचत होती है।

पालम से दिल्ली कैंट के बीच जाम की समस्या से त्रस्त हुए चालक, घंटों जाम में बीत रहा स्कूली बच्चों का समय

नई दिल्ली। सड़कों पर वाहनों के बढ़ रहे दबाव व यातायात पुलिस की सुस्ती के कारण पालम फ्लाईओवर से दिल्ली छावनी स्थित रक्षा संपदा भवन तक करीब पांच किलोमीटर का हिस्सा व्यस्त समय के दौरान जाम की चपेट में रहता है। यह हाल तब है जब दक्षिण-पश्चिमी व पश्चिमी दिल्ली की करीब 20 लाख से अधिक आबादी रोजाना इस रास्ते से गुजरती है। एयरपोर्ट को इस क्षेत्र से जोड़ती है। जाम के कारण सुबह-शाम आधा से एक घंटे का समय लोगों का इस जाम में बीत रहा है। प्रभावितों में नौकरीपेशा से लेकर स्कूली बच्चे तक शामिल हैं। स्थिति तब ऐसी है जब इस रूट पर मेट्रो की भी सुविधा है। जाम के कारण न सिर्फ ईंधन का भारी नुकसान हो रहा है बल्कि वायु प्रदूषण की समस्या भी इस क्षेत्र में बढ़ गई है। हरित क्षेत्र होने के कारण जो कि पहले यह समस्या नहीं थी।

फ्लाईओवर की चौड़ाई है कम

महावीर एन्क्लेव की तरफ से आने वाला वाहनों का हुजूम, इसमें निजी वाहनों के साथ स्कूली बस भी शामिल है, सर्विस लेन से पालम फ्लाईओवर पर चढ़ता है। दूसरा मंगलापुरी की तरफ से आने वाले वाहन भी दिल्ली कैंट जाने के लिए यही से फ्लाईओवर पर चढ़ते है। पर यहां फ्लाईओवर की चौड़ाई कम है और उस पर से फ्लाईओवर के ऊपर बेघर लोगों का जमघट जमा रहता है। इसके चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है और धीरे-धीरे जाम की समस्या खड़ी हो जाती है।वही कुछ वाहन चालक पालम से फ्लाईओवर पर चढ़ते है और यहां भी फ्लाईओवर की चौड़ाई उतनी अधिक नहीं है। इसके अलावा यहां फ्लाईओवर की तरफ जाने वाली सड़क जर्जर है। उधर, पालम रेलवे स्टेशन पर ट्रैन के परिचालन के कारण काफी देर चालकों को इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में चालक फ्लाईओवर के इस्तेमाल पर अधिक जोर देते है। सुबह सात बजे से ही यहां जाम की समस्या खड़ी हो जाती है, जो दस बजे तक बनी रहती है। देखते ही देखते मंगलापुरी, द्वारका सेक्टर-1, पालम की मुख्य सड़कें व गलियां पूरी तरह से जाम की जद में आ जाती है। स्थिति यह हो जाती है कि स्थानीय लोग छोटे-मोटे काम के लिए वाहन लेकर भी घरों से नहीं निकल पाते है। वाहन के हार्न के शोर से न सिर्फ स्थानीय निवासी बल्कि चालक खुद परेशान हो जाते है।

चालकों ने बताया कि एक तरफ पेट्रोल व सीएनजी की कीमतें आसमान छू रही है और जाम के कारण दो गुना गैस व पेट्रोल की बर्बादी हो रही है। इससे हमें आर्थिक व मानसिक दोनों रूपों में नुकसान हो रहा है। जाम के कारण कई बार लोगों की फ्लाइट तक छूट जाती है, क्योंकि आइआइजी की तरफ जाने वाली यह मुख्य सड़क है। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि कई बार रात को 11 बजे तक भी लोग यहां जाम में फंसे रहते हैं।

नौकरीपेशा लोगों के समय में हो बदलाव

यातायात पुलिस अधिकारियों की माने वर्ष 2010 में पालम फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, उस समय वाहनों की संख्या सड़कों पर कम थी और महज 15 मिनट में चालक धौला कुआं तक पहुंच जाता था। पर फिलहाल दिल्ली में देश की अन्य मेट्रोपोलिटन राज्यों से अधिक वाहन पंजीकृत है और इस कारण दिल्ली में जाम एक बड़ी व भयावह समस्या है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले- 2024 में यहां भी होंगी अमेरिका जैसी सड़कें, चलेगी ड्रोन टैक्सी

बागपत में एलिवेटिड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 में यहां भी अमेरिका जैसी सड़कें होंगी और ड्रोन टैक्सी चलाने की योजना है। यही नहीं पराली से बायो ईंधन बनाने की योजना है।

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को गणेशपुर में आकर निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की शिवालिक पहाड़ियों में बन रही एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर गणेशपुर में बने हेलीपैड पर दोपहर ढाई बजे उतरा। इसके बाद वे दिल्ली देहरादून कॉरिडोर तथा एलिवेटिड रोड का निरीक्षण करने निकले। मात्र बीस मिनट के संक्षिप्त दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री लौट जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 में अमेरिका जैसी सड़के यहां भी होगी। पराली से बायो ईंधन बनाने की योजना है। ड्रोन टैक्सी भी चलेगी। कहा कि गाड़ी में चिप लगेगी और सड़क पर चलते ही टोल कट जाएगा।

उन्होंने कहा कि हाईवे किनारे पहले बार बर्ड पार्क बनाए जाएंगे, जिसमे फल के पेड़ लगाए जायेंगे। यह भी योजना है की उन फलों को इंसान नहीं खाएंगे बल्कि उन्हें पक्षी खाएंगे। ये पेड़ तकरीबन तीन मीटर के दायरे में लगाए जाएंगे। पिलर पर पेंटिंग की जा सकती है। पहली बार बर्ड पार्क बनने जा रहे है।

अतिक्रमण को लेकर गडकरी ने कहा कि अतिक्रमण तोड़ दो, हाईवे पर अगर कहीं अतिक्रमण है तो तोड़ना होगा। हाईवे पर हादसे नहीं होने चाहिए। हाईवे अच्छे होने चाहिए। कहा कि हाईवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था की जा रही है। कई जगह हो चुका है। एक्सेस कंट्रोल हाईवे से हादसे में कमी आएगी।

जम्मू कश्मीर: सड़क मंत्रालय की सलाहकार समिति के सांसद आएंगे सोनमर्ग, इन मुद्दों पर करेंगे बैठक

जम्मू। जम्मू कश्मीर हाल ही में संसदीय समितियों के लिए बैठकों और अध्ययन दौरों के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। गुरुवार को समाप्त होने वाले बजट सत्र के साथ, एक संसदीय समिति मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के पर्यटन स्थल सोनमर्ग में अपनी बैठक करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़ी संसद के सदस्यों की सलाहकार समिति 9 से 11 अप्रैल तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने पहुंचेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली समिति और लोकसभा और

राज्यसभा के सांसद कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोनमर्ग में अपनी बैठक करने जा रहे हैं। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के तीन सांसद शामिल हैं। बैठक के दौरान वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन, भारतमाला परियोजना की समीक्षा और नई बस पोर्ट नीति के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में चर्चा के लिए अन्य मुद्दे भी शामिल किए जा सकते हैं। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बैठक की मेजबानी के लिए कमर कस ली है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग और सड़क एवं भवन विभाग ने अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की निविदा

मेहरौना घाट से सीवान तक फोरलेन का निर्माण जल्द

पटना। रामजानकी मार्ग के अंतर्गत बिहार में प्रवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से सीवान तक 40.84 किलोमीटर फोरलेन निर्माण का काम जल्द ही शुरू होगा. इसके लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निविदा जारी कर दी है. निर्माण एजेंसी का चयन मई, 2023 के अंत तक कर लिया जाएगा. मंत्रालय ने निविदा भरने के लिए 16 मई तक का समय दिया है. यह सड़क एनएच 227-ए से जानी जाती है. एनएच 227-ए पर मेहरौना घाट से सीवान तक 40.84 किलोमीटर तक फोरलेन के निर्माण पर 721 करोड़ 78 लाख खर्च होंगे. मेहरौना घाट उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर देवरिया जिले के समीप अवस्थित है. हालांकि, यह सड़क एनएच 227-ए उत्तर प्रदेश के आयोध्या से शुरू होकर बिहार में पूर्वी चंपारण के मेहसी तक जाती है. मालूम हो कि रामजानकी मार्ग के अंतर्गत अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक 448 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. इसमें 436 किलोमीटर का हिस्सा भारत में और 12 किलोमीटर नेपाल में पड़ता है. बिहार की सीमा में मेहरौना घाट से नेपाल बोर्डर (भिट्ठा मोड़) तक 237 किलोमीटर फोरलेन का निर्माण होना है.

ढाई साल में निर्माण होगा पूरा

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निविदा में ही यह तय कर दिया है कि इस फोरलेन का निर्माण कार्य ढाई साल में पूरा कर लिया जाएगा. जिस भी निर्माण एजेंजी को यह काम सौंपा जाएगा, उसे ढाई साल का समय दिया जाएगा. अयोध्या से जनकपुर तक सीधी और बेहतर सड़क सेवा उपबल्ध कराने के मकसद से रामजानकी मार्ग के निर्माण की कवायद चल रही है.

गुजरात-असम सड़क से जुड़ता है एनएच 227-ए

एनएच 227-ए गुजरात से शुरू होकर असम तक जाने वाले एनएच 27 (3507 किमी) से भी जुड़ता है. इस तरह एनएच 227-ए उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के साथ-साथ गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य को भी जोड़ता है. इस सड़क के चौड़ीकरण होने से कई राज्यों के साथ ही नेपाल आने-जाने में भी काफी सुविधा होगी. लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा.

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

83% भारतीय मानते हैं कि जॉब इंटरव्यू में महिलाओं से उनकी शादी के बारे में पूछना गलत: सर्वे

सर्वे में कामकाजी युवाओं का मानना है कि कर्मचारियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर काम पर रखा जाना चाहिए न कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर. (फोटो- canva.com)सर्वे में कामकाजी युवाओं का मानना है कि कर्मचारियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर काम पर रखा जाना चाहिए न कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर. आज भी कुछ पैमाने हैं जिन पर महिला उम्मीदवारों को सिलेक्शन के वक्त काबलियत होते हुए भी पीछे कर दिया जाता है. ये सच है कि अधिकांश भारतीय कंपनियां और भर्तीकर्ता (companies and recruiters) महिला उम्मीदवारों से उनकी वैवाहिक स्थिति (marital status) के बारे में पूछते हैं. अक्सर महिला उम्मीदवारों का सामना कुछ ऐसे सवालों से होता है, जो उन्हें असहज कर देते हैं. जैसे- क्या आप शादीशुदा हैं? या आप कब तक शादी करने का प्लान कर रही हैं? आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड (competitive world) में हर कदम पर आपको बेहतर करने की जरूरत होती है. चाहे कोई महिला हो या पुरुष, हर कोई इतनी काबलियतों के साथ मैदान में हैं कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट को चुनना एक चुनौती से कम नहीं है. लेकिन आज भी कुछ पैमाने हैं जिन पर महिला उम्मीदवारों को सलेक्शन के वक्त काबलियत होते हुए भी पीछे कर दिया जाता है. ये सच है कि अधिकांश भारतीय कंपनियां और भर्तीकर्ता (companies and recruiters) महिला उम्मीदवारों से उनकी वैवाहिक स्थिति (marital status) के बारे में पूछते हैं. अक्सर महिला उम्मीदवारों का सामना कुछ ऐसे सवालों से होता है, जो उन्हें असहज कर देते हैं. जैसे- "क्या आप शादीशुदा हैं?" या "आप कब तक शादी करने का प्लान कर रहे हैं?" लेकिन शायद ही कभी पुरुष आवेदकों के सामने इन सवालों को रखा जाता है.

बेटरहाफ डॉट एआई

(Betterhalf.ai)द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे में कामकाजी युवाओं का मानना है कि कर्मचारियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर काम पर रखा जाना चाहिए न कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर. युवाओं की ये राय है कि शादी और काम बिना किसी रुकावट के जारी रह सकते हैं.

सर्वे में क्या निकला

भारतीय कंपनियां आज ग्रोथ और इनोवेशन के मामले में दुनिया की अग्रणी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं.लेकिन जब उनकी मानसिकता की बात आती है, तो कंपनियां अभी भी महिला कर्मचारियों के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति और उम्र के आधार पर भेदभाव करना पसंद करती हैं, भारतीय युवाओं का दावा है.सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार, 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं (respondents) का मानना है कि भर्ती करने वाले महिला उम्मीदवारों से उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में सवाल पूछते हैं, जो कि अनुचित है.

ऑनलाइन सर्वे के निष्कर्षों ने ये भी खुलासा किया कि 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शादी करने से पहले पुरुषों और महिलाओं दोनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए. दूसरी ओर, केवल 6 प्रतिशत ही इस बात से सहमत थे कि पुरुषों को एकमात्र रोटी कमाने वाला होना चाहिए. इसके अलावा, 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि महिलाएं कमाने वाली हो सकती हैं.सर्वे से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि युवा कामकाजी पेशेवरों के दिमाग में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जो मानते हैं कि शादी से पहले वित्तीय स्वतंत्रता आवश्यक है.

बेटरहाफ डॉट एआई के सीईओ और सह-संस्थापक, पवन गुप्ता (Pawan Gupta) ने सर्वे के निष्कर्षों पर बात करते हुए कहा, "महिलाएं दुनिया भर में अपने वर्कप्लेस में नई-नई उंचाईयां छू रही हैं, लेकिन इस तरह की प्रथाएं प्रतिभाशाली महिलाओं को नौकरी खोजने से रोक सकती हैं. शादी पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है, फिर भी पुरुषों को ऐसे इंटव्यू प्रश्नों के अधीन नहीं किया जाता है. जैसा कि वक्त बदल रहा है और प्रगतिशील संगठन (progressive organizations) सामने आ रहे हैं, उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाना चाहिए."

दुनियाभर में छोटी बच्चियों के लिए ये 3 चुनौतियां हैं डरावनी, बच्चियों को लेकर रहें अलर्ट

पूरी दुनिया में मानव तस्करी सबसे तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अपराधों में से एक बन गया है. इसमें अपराधी छोटी बच्चियों को उनके घरों और उनके परिवार से दूर बहला फुसलाकर ले जाते हैं और उन्हें ऐसे काम में लगाते हैं जो उनके लिए शारीरिक रूप से हानिकारक होता ही है, भावनात्मक रूप से भी विनाशकारी होता है.

दुनियाभर में लाखों की तादात में ऐसी बच्चियां और महिलाएं हैं जो अपने बेसिक अधिकारों से भी बेदखल कर दी जाती हैं और उनके साथ हर तरह से भेदभाव किया जा रहा है. वे अपने परिवार व समाज से उपेक्षा की शिकार हो जाती हैं जिससे सबसे अधिक प्रभावित छोटी बच्चियां होती हैं जो अभी बचपन से बाहर भी नहीं निकली हैं. उन्हें नन्हीं सी उम्र में ही कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है. मुश्किल समस्या इसलिए भी है क्योंकि इस विकसित होती दुनिया में उनके सबसे करीबी लोग ही उसे बहला फुसलाकर ऐसे जघन्य अपनाध का शिकार बनाते हैं या इस गहरी खाई में झोंकने का काम करते हैं. कॉम्पैशन में छपे आर्टिकल के मुताबिक जानते हैं कि विकसित होती आज की दुनिया में भी छोटी लड़कियों के लिए सबसे बड़ी 3 चुनौतियां कौन सी हैं जिससे हमें एक परिवार, समाज और नागरिक होने के नाते उन्हें हर संभव बचाने की जरूरत है.

> "अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल तस्करी तब होती है जब बच्चों को उनके सुरक्षात्मक वातावरण से बाहर निकाल दिया जाता है और शोषण के उद्देश्य से उनका शिकार किया जाता है. पूरी दुनिया में मानव तस्करी सबसे तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अपराधों में से एक बन गया है. इसमें अपराधी छोटी बच्चियों को उनके घरों और उनके परिवार से दूर बहला फुसलाकर ले जाते हैं और उन्हें ऐसे काम में लगाते हैं जो उनके लिए शारीरिक रूप से हानिकारक होता ही है, भावनात्मक रूप से भी विनाशकारी होता है. मसलन, श्रम शोषण, यौन शोषण, जबरन शादी या गोद लेना, आपराधिक गतिविधियां आदि.

दुनियाभर की लड़कियों के लिए सबसे बड़ी 3 चुनौतियां

गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल तस्करी तब होती है जब बच्चों को उनके सुरक्षात्मक वातावरण से बाहर निकाल दिया जाता है और शोषण के उद्देश्य से उनका शिकार किया जाता है. पूरी दुनिया में मानव तस्करी सबसे तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अपराधों में से एक बन गया है. इसमें अपराधी छोटी बच्चियों को उनके घरों और उनके परिवार से दूर बहला फुसलाकर ले जाते हैं और उन्हें ऐसे काम में लगाते हैं जो उनके लिए शारीरिक रूप से हानिकारक होता ही है, भावनात्मक रूप से भी विनाशकारी होता है. मसलन, श्रम शोषण, यौन शोषण, जबरन शादी या गोद लेना, आपराधिक गतिविधियां आदि.

बाल विवाह

गर्लनॉटब्राइडके मुताबिक, हर 3 सेकेंड में 1 लड़की बाल विवाह की शिकार हो रही है. 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह को बाल विवाह माना जाता है जिससे लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी गुजरना पड़ना है. लेकिन लड़कियां इससे अधिक प्रभावित होती हैं. दुनिया भर में, आज 70 करोड़ से अधिक महिलाओं की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी गई. हालांकि इस पर काफी संस्थाएं काम कर रही हैं और लोगों में बाल विवाह के प्रति जागुरकता फैला रही है, लेकिन इसके बावजूद यह प्रथा अभी तक समाप्त नहीं हुई है. साउथ अफ्रिका, सहारा और एशिया के देशों में यह अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है.

महिला जननांग विकृति

यह एक नॉन मेडिकल कल्चर और सामाजिक प्रथा है जिसमें लड़कियों के जननांग अंगों को हटाने की परंपरा है. महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation)15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों पर किया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, आज जीवित 200 मिलियन से अधिक लड़कियों और महिलाओं ने अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 30 देशों में FGM का अनुभव किया है जहां यह एक प्रचलित प्रथा रही है और आज भी की जा रही है. यह शारीरिक और मानसिक रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए काफी विनाशकारी होती है. यह एक कष्टदायी तरीका है जिसमें रक्तस्राव, संक्रमण, मूत्र प्रतिधारण और खुले घाव होने की संभावना काफी अधिक होती है. एफजीएम से बचे लोगों को बार-बार पेशाब आना, मूत्र पथ के संक्रमण, अल्सर, बांझपन, बच्चे के जन्म में जटिलता और नवजात मृत्यु की संभावना भी बहुत अधिक हो सकती है. इस प्रथा की वजह से हर साल हजारों बच्चों के जीवन का दावा करता है.

70% महिलाएं खुद पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ रहती हैं चुप- सर्वे

एनएफएचएस-5 (**NFHS** -5) यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (**National Family Health Survey** 5) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 11 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की करीब 70 फीसदी महिलाएं खुद पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कभी नहीं बताती हैं और ना कभी किसी से किसी तरह की मदद लेती हैं.

आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं सहनशील होती हैं, वो सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती हैं. भारतीय परिपेक्ष में देखें तो बहुत हद तक ये बात सच भी है. हमारे समाज में शुरू से ही महिलाओं को कम बोलने ही हिदायत दे दी जाती है. बचपन से लेकर बड़े होने तक और बड़े होने से लेकर बुजुर्ग होने तक उसे कदम-कदम पर इन्हीं हिदायतों और पाबंदियों में जीना होता है. इसीलिए महिला के लिए सहनशील होने की उपमा लगा दी गई लेकिन अगर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी जाए, तो ये जानलेवा हो सकती है. ऐसी सहनशीलता देश और पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है. एनएफएचएस-5 (**NFHS** -5) यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (**National Family Health Survey** 5) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 11 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की करीब 70 फीसदी महिलाएं खुद पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कभी नहीं बताती हैं और ना कभी किसी से किसी तरह की मदद लेती हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में असम-बिहार, मणिपुर, सिक्किम और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश ऐसे हैं जिनमें हिंसा सहने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक हैं. इन राज्यों में ऐसी महिलाओं की संख्या 80 प्रतिशत से ज्यादा है. वहीं त्रिपुरा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हर जुल्म को चुपचाप सह लेने वाली महिलाओं की सख्या 70 फीसदी से ज्यादा है.

मदद मांगने वाली महिलाएं

अगर बात जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने या मदद मांगने की करें तो ये आंकड़े काफी निराशाजनक है. एनएफएचएस-5 (**NFHS** -5) के अनुसार, देश में 10 फीसदी से कम ही ऐसी महिलाएं हैं, जो खुद पर होने वाले अत्याचारों को लेकर दूसरों से मदद मांगती हैं. असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां 10 फीसदी से भी कम महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर मददगार तलाशती हैं.

मदद के लिए पहला दरवाजा

इस सर्वे के दौरान हिंसा और अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वो मदद के लिए सबसे पहले अपने परिवार वालों, पड़ोसी, पुलिस, वकील और धर्म गुरुओं तक की मदद लेती हैं.

यहां लगती है सबसे ज्यादा चोट

सर्वे के अनुसार, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सबसे ज्यादा चोट आंखों पर, हड्डियों के टूटने, जलने, कटने और दांत तोड़े जाने जैसी घटनाओं में आती है.

लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने के लिए महिलाएं ज़रूर लें ये 6 विटामिंस

महिलाओं को विटामिन सी, डी, फोलेट, आयरन आदि का सेवन हर दिन करना चाहिए.महिलाओं को विटामिन सी, डी, फोलेट, आयरन आदि का सेवन हर दिन करना चाहिए.

महिलाएं अक्सर घर के काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि खुद की सेहत, खानपान के प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन आपका ऐसा करना आपकी ही सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. आप लंबी उम्र तक हेल्दी रहना चाहती हैं, तो कुछ विटामिंस का सेवन प्रतिदिन ज़रूर करें.

महिलाएं घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों को संभालते-संभालते अपनी तरफ ध्यान देना भूल जाती हैं. उन्हें जितनी चिंता अपने परिवार की सेहत की रहती है, खुद की सेहत के प्रति लापरवाह हो जाती हैं. यदि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को अकेले संभालती हैं, तो ज़रूरी है अपनी सेहत के प्रति भी उतनी ही गंभीर रहें, क्योंकि आप ही अस्वस्थ रहेंगी, तो फिर घर-परिवार, ऑफिस के कामों को कैसे संभाल पाएंगी. बढ़ती उम्र में बेहद ज़रूरी है कि आप हर उन पौष्टिक चीजों को डाइट में शामिल करें, जिससे आप फिट और हेल्दी बनी रहें, ना सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी. हेल्दी डाइट लेने के साथ ही आप कुछ विटामिंस का डेली डोज भी उम्र के मुताबिक ज़रूर लें, ताकि हड्डियों से लेकर स्किन, बाल, आंखें सभी स्वस्थ और फिट रहें. यहां जानें, महिलाओं को किन विटामिंस को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

विटामिन बी6 और विटामिन डी

मेडिकलन्यूजटुडे में छपी एक खबर के अनुसार, 19 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं, शिशु को स्तनपान कराने या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं को न्यूट्रिशनल डेफिसिएंसी अक्सर होती है. इसमें विटामिन बी6 और विटामिन डी की कमी सबसे अधिक होती है. ऐसे में इस उम्र की महिलाओं को प्रतिदिन 15 मिलीग्राम विटामिन डी का सेवन जरूर करना चाहिए. वहीं, विटामिन बी6 लगभग 1.3 मिलीग्राम, प्रेग्नेंसी में लगभग 1.9 एमजी और ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं को लगभग 2 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन बी6 की जरूरत होती है.

आयोडीन की भी होती है ज़रूरत

गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन की ज़रूरत बहुत होती है. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा वर्ष 2012 में कराए गए एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, अध्ययन में शामिल किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में 20-39 वर्ष की आयु की महिलाओं में आयोडीन का स्तर कम था. इनमें से अधिकतर महिलाएं गर्भवती थीं. इस उम्र की महिलाओं के लिए प्रतिदिन 150 मिग्रा आयोडीन, प्रेग्नेंट महिला के लिए 220 मिलीग्राम और स्तनपान कराने वाली महिला के लिए 290 एमजी आयोडीन का इनटेक बहुत आवश्यक होता है. हालांकि, बिना डॉक्टर की सलाह के आयोडीन सप्लिमेंट्स लेने से बचना चाहिए वरना थायरॉएड हेल्थ पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है.

फोलेट या विटामिन बी9 महिलाएं अवश्य लें

फोलेट को विटामिन बी9 भी कहा जाता है, जो रिप्रोडक्टिव वर्षों के दौरान बेहद ज़रूरी होता है. यह भ्रूण में होने वाली मस्तिष्क और रीढ़ संबंधित जटिलताओं के जोखिम को कम करता है. लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और प्रोटीन पाचन में सहायता करता है. यदि आप प्रेग्नेंट हैं, तो शरीर में विटामिन बी9 की कमी ना होने दें.

आयरन है बेहद ज़रूरी

अधिकतर महिलाओं को आयरन की भी कमी खूब होती है. आयरन एक प्रकार का खनिज है, जो रिप्रोडक्टिव आंगों और उनके बेहतर तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी होता है. साथ ही शरीर में ऊर्जा का निर्माण, घावों को भरने, इम्यून फंक्शन, रेड ब्लड सेल के बनने, विकास आदि के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है. 19 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिदिन 18 मिलीग्राम आयरन लेने की ज़रूरत होती है.

विटामिन सी बूस्ट करे इम्यूनिटी

विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर आपको कई तरह के इंफेक्शन, रोगों से बचाने में कारगर होता है. लंबी उम्र तक चाहती हैं आपकी त्वचा, बाल जवां, झुर्रियां रहित और स्वस्थ रहें, तो विटामिन सी युक्त चीजों को डाइट में प्रतिदिन शामिल करें. इससे आंखों की सेहत भी अच्छी बनी रहती है.

विटामिंस की कमी दूर करने के लिए फूड्स

फोलेट- इसकी कमी शरीर में ना हो, इसके लिए आप डाइट में चावल, एवोकाडो, ब्रोकली, संतरा, फोर्टिफाइड नाश्ते में खाया जाने वाला अनाज, साग आदि शामिल करें.

विटामिन डी- हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है. इसके लिए आप फैटी फिश, अंडे की जर्दी, लिवर, मशरूम आदि खाएं.

आयोडीन- महिलाओं को आयोडीन की पूर्ति करने के लिए अंडा, अनाज से बने प्रोडक्ट्स, आयोडाइज्ड नमक, सीफूड, बिना चीनी वाले डेयरी उत्पाद आदि का सेवन करना चाहिए.

आयरन- अक्सर महिलाओं को आयरन की कमी होती है. आयरन की कमी दूर करने के लिए रेड मीट, सीफूड, दालें, सोयाबीन्स, साग, अंडा आदि खाएं.

कैल्शियम- डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड दूध, जूस, सैल्मन मछली, टोफू, केल आदि खाकर कैल्शियम की कमी दूर कर सकती हैं.

सुरक्षा के भारी इंतजाम के बीच जहांगीरपुरी में निकली शोभा यात्रा, छावनी में तब्दील रहा इलाका

दो हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पुलिस ने केवल 200 मीटर तक ही यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। यात्रा के दौरान पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहे साथ ही ड्रोन से भी शोभा यात्रा पर नजर रखी गई।

नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी मौजूदगी में गुरुवार को जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में दो सौ मीटर तक ही दो रूटों पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए संवेदनशील इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा इलाके में दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात किए गए। उस इलाके में लोगों को गली से बाहर निकालने से मना किया गया और कुछ गेटों पर ताले लगाए गए। भाजपा नेता कपिल मिश्रा के यात्रा में पहुंचने की घोषणा के बाद पुलिस सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई। पुलिस अधिकारियों ने कपिल मिश्रा से बात की और उनको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा में शामिल होने की इजाजत भी दी।

इससे पहले चार अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को आयोजकों हिंदू वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस के पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद पुलिस ने दो रूटों पर दो सौ मीटर तक ही शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। शोभा यात्रा को एस ब्लॉक जहांगीरपुरी से जहांगीरपुरी थाना के पास और ई ब्लॉक से कुशल चौक तक अनुमति दी गई। इससे आगे मस्जिद रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और आगे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी गई।

सुबह से ही शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग जहांगीरपुरी के रामलीला मैदान के पास पहुंचने शुरू हो गए। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग अपने हाथों में केशरिया पताका लेकर जय श्रीराम का उद्घोष कर रहे थे। हिंदू वाहिनी के आयोजक जहांगीरपुरी के रामलीला मैदान में पूजा पाठ करने के बाद दोपहर में शोभा यात्रा शुरू की। इन्हें एस ब्लॉक से जहांगीरपुरी थाने तक दो सौ मीटर जाने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान पूरे रूट के दोनों तरफ दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान को तैनात थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो हिंदू संगठन को यहां शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। एक संगठन में करीब दो सौ और दूसरे संगठन को करीब पांच सौ लोगों को यात्रा में शामिल करने की इजाजत दी गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग नाचते गाते और जयकारा करते हुए यात्रा संपन्न की। दोपहर दो बजे से विश्व हिंदू परिषद के आयोजकों ने ई ब्लॉक जहांगीरपुरी में जमा हुए और फिर पूजा पाठ करने के बाद कुशल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान यात्रा में शामिल लोग ने जय श्रीराम के नारे लगाए और नाचते गाते कुशल चौक पर पहुंचे। पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग की थी। जिसके आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। यात्रा के पूरे रास्ते में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे। पुलिसकर्मी घरों के छतों से भी सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। जिला पुलिस उपायुक्त जीतेंद्र मीना खुद सुरक्षा बल के साथ यात्रा में चल रहे थे।

यात्रा के दौरान छावनी में तब्दील हो गया जहांगीरपुरी

दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आयोजकों की सलाह पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है, लेकिन पुलिस सुरक्षा के इंतजाम कर यह सुनिश्चित कर रही है कि इलाके में अमन चैन बरकरार रहे। पुलिस जहांगीरपुरी के संवेदनशील इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी से लोगों पर निगरानी रख रही है। वहीं उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त जीतेंद्र मीना ने बताया कि जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल के चार कंपनियों को तैनात किया गया। हर स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद लिया जा रहा है।

सी ब्लॉक के लोगों को गलियों में किया गया बंद

शोभा यात्रा को लेकर सी ब्लॉक में रहने वाले लोगों को गलियों में ही रहने को कहा गया। इसी ब्लॉक में पिछले साल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए सी ब्लॉक के सभी गेटों पर ताला लगा दिया। पिछले साल हिंसा को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर ली। यहां लॉकडाउन के हालात थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के मददेनजर बुधवार को कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि यात्रा के दौरान लोग यहां से बाहर न निकलें।

भाजपा नेता कपिल मिश्रा के जहांगीरपुरी पहुंचने से पुलिस हुई सतर्क

भाजपा नेता कपिल मिश्रा के जहांगीरपुरी पहुंचने की घोषणा से पुलिस सतर्क हो गई। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि वह शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जहांगीरपुरी जा रहे हैं। पिछले साल की हिंसा को देखते हुए पुलिस ने कपिल मिश्रा को रोका। पुलिस अधिकारियों ने उनसे बातचीत की। बाद में वह जहांगीरपुरी पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। कपिल मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यात्रा हो रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस बधाई के पात्र हैं। वह भी यात्रा में पुलिस की दी हुई मर्यादा का पालन करेंगे।

जहांगीरपुरी में पिछले साल हुई थी हिंसा

जहांगीरपुरी में पिछले साल 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर बवाल हुआ था। इस इलाके से शोभा यात्रा निकल रही थी इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उसपर पथराव कर दिया था। जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इसमें आठ पुलिसकर्मी समेत नौ लोग घायल हो गए थे। उस दौरान पुलिस ने शोभा यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं दी थी।

इनसाइड

जहांगीरपुरी में शोभायात्रा में पुलिस के साथ पहुंचे कपिल मिश्रा

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुरुवार को शोभायात्रा निकाली जा रही है। शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, हालांकि अब पुलिस के साथ वह जहांगीरपुरी की शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। शोभायात्रा को देखते हुए इलाके में चप्पे-चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रही है। इधर एच ब्लॉक में शोभायात्रा को रद्द कर दिया गया है। 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर कार्यक्रम चल रहा है। शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन अब वह पुलिस के साथ दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 5 मिनट पहले ही कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा था कि वह जहांगीरपुरी आ रहे हैं। बता दें कि पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से जहांगीरपुरी इलाके में शोभायात्रा को निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। खास बात है कि सीएए के विरोध के दौरान इसी इलाके में हिंसा हुई थी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि आज 2 शोभायात्राओं की अनुमति थी। एक यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दूसरी यात्रा के लिए तैयारी जारी है, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वहीं स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव पर शहर भर में रंगारंग कार्यक्रम होंगे। हमारे पास अर्धसैनिक बलों की रणनीतिक तैनाती है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस की उम्मीद वाले सभी स्थान सुरक्षित हों।

सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। दोनों ही मामलों में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

नई दिल्ली। कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी डाली हुई है। इस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सिसोदिया की याचिका पर जवाब मांगा है।

इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। दोनों ही मामलों में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया 26 फरवरी से गिरफ्तार हैं।

मालिक ने बैंक में जमा करने के लिए दिए 35 लाख रुपये, कर्मचारी पूरी रकम लेकर हुआ नौ दो ग्यारह

लाहौरी गेट इलाके में कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को फर्म के खाते में 35 लाख रुपये में जमा करने के लिए दिए लेकिन रास्ते में एक कर्मचारी ने दूसरे को कोल्ड ड्रिंक लाने को भेज खुद पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया।

नई दिल्ली। लाहौरी गेट इलाके में कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को फर्म के खाते में 35 लाख रुपये में जमा करने के लिए दिए, लेकिन रास्ते में एक कर्मचारी ने दूसरे को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए भेजा और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद 72 घंटे में उत्तरी जिला पुलिस ने आरोपित मुकेश कुमार गुप्ता को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार कर चोरी के सारे रुपये बरामद कर लिए हैं।

साथी को भेजा कोल्ड ड्रिंक लाने

डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि कारोबारी महेंद्र कुमार गुप्ता ने गत सोमवार को अपने कर्मचारी पवन और मुकेश गुप्ता को अपनी फर्म के बैंक खाते में 35 लाख रुपये जमा करने के लिए दिए थे। अपनी शिकायत में महेंद्र ने बताया कि रास्ते में पवन ने उन्हें फोन कर बताया कि मुकेश ने रास्ते में उसे कोल्ड ड्रिंक लाने को भेजा। जब वह वापस आया तो वहां पर मुकेश नहीं मिला। वह पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया।

पुलिस ने की 70 सीसीटीवी कैमरों की जांच

मामले की जांच के लिए एसएचओ विजेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआइ देवेंद्र अंतिल, एएसआइ सत्यपाल समेत अन्य पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपित के भागने की दिशा में लगे करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की जांच की, इससे पता चला कि आरोपित लाहौरी गेट चौक से ई-रिक्शा लेकर अजमेरी गेट के पास उतरा फिर वहां से आटो रिक्शा से आगे गया।

हापुड़ से किया गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की जांच में सराय काले खां तक आरोपित के बारे में जानकारी मिली, लेकिन इसके आगे की जानकारी पुलिस नहीं मिल सकी। पुलिस ने आरोपित मुकेश के स्वजन और जानकारों से पूछताछ की, जिसके बाद बृहस्पतिवार की सुबह आरोपित मुकेश को हापुड से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर उसके पास से चोरी के 35 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

दिल्ली शराब घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सिसोदिया का नहीं है नाम

दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने चार्जशीट में राजेश जोशी राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ कोर्ट में दार्जशीट फाइल की है।

नई दिल्ली। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने चार्जशीट में राजेश जोशी, राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ कोर्ट में दार्जशीट फाइल की है। हालांकि, ईडी को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिजनेसमैन अमनदीप ढाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना है।

बता दें कि बुधवार को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया था, इसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी है। इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया इसके साथ ही सीबीआई मामले में भी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सिसोदिया

आबकारी नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले में जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान के मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जवाब मांगा है।

26 फरवरी को सिसोदिया की हुई थी गिरफ्तारी

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

पार्टी ने लगातार कई ट्वीट करके अलग-अलग राज्यों में पोस्टर चिपकाने के अपने अभियान की जानकारी दी।

कौन है मेट्रो की वायरल मिस्ट्री गर्ल रिदम चनाना, पहनावे को लेकर आई थीं चर्चा में

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं जिसमें एक लड़की दिल्ली मेट्रो में बिकनी और मिनीस्कर्ट पहने सफर करती नजर आ रही है। आइए जानते हैं आखिर वीडियो में दिख रही ये वायरल लड़की कौन है?

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। सभी सोशल मीडिया यूजर्स इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर दिल्ली मेट्रो में बोल्ड कपड़ों में सफर कर रही ये मिस्ट्री गर्ल आखिर कौन है। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की दिल्ली मेट्रो में बिकिनी पहनकर सफर करते देखी जा रही है।

सोशल मीडिया यूजर्स इस लड़की के पहनावे को लेकर खूब ट्रोल कर रहे हैं। यह पब्लिसिटी स्टंट है या फैशन च्वाइस? सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक बहस छिड़ गई है। ट्रोलर्स ने लड़की के पहनावे को देखकर उसे ₹दिल्ली मेट्रो वाली 'Urfi Javed' का नाम दिया है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उसे टीवी अभिनेत्री उर्फी जावेद से प्रेरित बता रहे हैं। उर्फी जो अपने बोल्ड फैशन सेंस के लिए काफी लोकप्रिय हैं। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो की इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में खुलासा हुआ। आइए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली मेट्रो की ये वायरल लड़की कौन है...?

दिल्ली मेट्रो में एक लड़की बिकनी और मिनीस्कर्ट पहने एक वीडियो में नजर आ रही है, जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरने वाली युवती की पहचान रिदम चनाना के रूप में की गई है। ट्रोलर्स के अलावा कुछ लोगों को यह जानने में दिलचस्पी है आखिर वह कौन है और वह इस तरह से क्यों कपड़े पहनेगी।

इसे लेकर मिस्ट्री गर्ल रिदम चनाना ने कहा कि मैं क्या पहनना चाहती हूं यह मेरी च्वाइस है। मैं यह किसी पब्लिसिटी स्टंट या प्रसिद्ध होने के लिए नहीं कर रही हूं। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। चनाना ने आगे कहा कि उनकी फैशन च्वाइस किसी भी तरह से उर्फी जावेद से प्रेरित नहीं हैं। हाल ही में एक दोस्त ने उनके बारे में मुझे बताया और उनकी तस्वीर दिखाई।

रिदम चनाना ने बताया कि वह काफी समय से ऐसे कपड़े पहन रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। यह पहनावा अपनाने में मुझे काफी वक्त लगा है। मैं भी एक रूढ़िवादी परिवार से आती हूं जहां मुझे वह करने की अनुमति नहीं थी जो मैं चाहती थी। इसलिए एक दिन, मैंने फैसला किया कि मैं अब वही करूंगी जो मैं चाहती हूं क्योंकि यह मेरा जीवन है। मैं कई महीनों से ऐसे कपड़े पहन रही हूं। यह अब चर्चा का विषय बन गया है।

रिदम ने यहां तक कहा कि ₹यह अजीब है कि डीएमआरसी अब मेट्रो के अंदर वीडियोग्राफी नहीं करने के अपने ही नियम को भूल गई है। अगर उन्हें मेरी पोशाक से समस्या है, तो उन्हें इसे शूट करने वालों से भी समस्या होनी चाहिए।

DMRC ने की मर्यादित पोशाक पहनने की अपील

मेट्रो में बिकनी पहनकर सफर करती युवती का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से मर्यादित पोशाक पहनने की अपील की है। जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसके साथ ही डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल निगम) ने मेट्रो में सफर के दौरान यात्रियों से अपने आचरण को मर्यादित बनाए रखने की सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहर भी छिड़ी हुई है। कई लोगों ने ट्वीट कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम मेट्रो में युवती के इस तरह के पहनावे को आपत्तिजनक बता रहे हैं। हालांकि वह काफी समय से ऐसी ड्रेस पहन रही हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे पहनावे में कई फोटोज और वीडियो देखे जा सकते हैं।

अधिवक्ता और रोडवेज कर्मियों में मारपीट, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन

परिवहन विशेष संवाददाता

गाजियाबाद। हापुड़ में अधिवक्ता व रोडवेज कर्मियों में मारपीट के मामले में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई से नाराज रोडवेज कर्मियों ने गुरुवार सुबह चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों ने बसों को डिपो में खड़ा कर नारेबाजी शुरू कर दी। बुधवार को कंडक्टर सीट पर बैठने को लेकर एक अधिवक्ता के बहनोई व परिचालक का विवाद हो गया था। जिसके बाद मामले की जानकारी करने हापुड़ डिपो पहुंचे अधिवक्ताओं और रोडवेज कर्मियों में मारपीट हो गई थी। जिसमें 2 अधिवक्ता घायल हो गए थे।

अधिवक्ताओं ने रोडवेज कर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार सुबह मामले में एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक बसें डिपो के अंदर बंद रहीं और रोडवेज कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की।

इस दौरान विभिन्न रूटों पर यात्रा के लिए पहुंचे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डग्गामार के माध्यम से लोग गंतव्य को रवाना हुए। करीब 3 घंटे के हंगामे के बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने रोडवेज कर्मियों को रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया।

जिसके बाद रोडवेज कर्मियों ने सेवा बहाल कर दी। पुलिस को कार्रवाई के लिए दोपहर तक का समय दिया गया है। दोपहर तक रिपोर्ट दर्ज ना होने पर दोबारा चक्का जाम की चेतावनी दी है।

इनसाइड

पिटाई के पीड़ित से कोतवाली में जबरन समझौता लिखवाने का आरोप

पीड़ित का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। मूलरूप से बिहार के रहने वाला मुकेश नामक युवक बुधवार रात सेक्टर-62 से अपने घर वापस लौट रहा था।

नोएडा। सेक्टर-58 कोतवाली क्षेत्र में एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने युवक से मारपीट कर उसका सिर फोड़कर शर्ट फाड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के दो लोगों को कोतवाली ले गई। जहां जबरन समझौता लिखवा लिया गया। घर पहुंचने के बाद युवक ने वीडियो बनाकर घटना की जानकारी दी। पीड़ित का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। मूलरूप से बिहार के रहने वाला मुकेश नामक युवक बुधवार रात सेक्टर-62 से अपने घर वापस लौट रहा था। सेक्टर-62 में शंकर फास्ट फूड के मालिक समेत 10-15 लड़कों ने मुकेश को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि उसके पास मौजूद 25 हजार रुपये की नकदी भी निकाल ली। जब पीड़ित शिकायत लेकर सेक्टर-62 स्थित एनआइबी पहुंचा तो चौकी इंचार्ज ने घायल युवक का मेडिकल कराने के बजाय धमकाकर भेज दिया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने डरा धमकाकर और जेल भेजने की धमकी देकर फैसला लिखवा लिया।

राष्ट्रीय ड्रॉप रोबॉल में छाए गाजियाबादी, तीसरे स्थान पर रही यूपी

गाजियाबाद। राष्ट्रीय सब-जूनियर बालक वर्ग ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए जनपद के खिलाड़ियों का हुनर देखने को मिला। हरिद्वार में हुई प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। टीम में गाजियाबाद के खिलाड़ी लवनीश, लक्ष्य सिंघल, आयुष और चिराग नागर ने जीत में अहम भूमिका निभाई।

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान केरल और दूसरा स्थान तेलंगाना की टीम ने पाया। बीते साल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी बालक वर्ग की टीम ने दूसरा स्थान पाया था। उत्तर प्रदेश ड्रॉप रोबॉल एसोसिएशन के सचिव राहुल देव गौतम ने बताया कि बालक वर्ग के सभी लीग मुकाबलों में टीम ने जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में यूपी ने हिमाचल प्रदेश को 2-0 से हराया। अगले संघर्षपूर्ण मुकाबले में टीम को केरल से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। टीम में वाराणसी के चार, मिर्जापुर के एक, चंदौली के दो और जौनपुर के दो खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक यादव ने टीम और कोच संजीवन पटेल को बधाई दी।

निगमकर्मी बनकर 30 टीन देने के नाम पर 60 हजार की ठगी

साहिबाबाद। नगर निगमकर्मी बनकर देशी घी और रिफाइंड के टीन बेचने के नाम पर 60 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। मिठाई वाले से पैसे लेकर ठग कार्यालय में गया और वहां से लापता हो गया। ठग के फरार होने पर मिठाई वाले को धोखाधड़ी होने का पता चला। मिठाई वाले ने साहिबाबाद थाना में शिकायत की है।

मोहननगर वर्ड स्क्वायर मॉल में अग्रवाल बीकानेर स्वीट्स संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल पर बुधवार को दो नगर निगम कर्मचारियों का फोन आया। नगर निगम मोहननगर जोनल कार्यालय आकर रिफाइंड के 30 टीन लेने को बोला था। वह टीन लेने के लिए मोहननगर कार्यालय पहुंचे तो गेट पर फोन करने वाला कथित कर्मचारी मिला। उसने दूसरे कर्मचारी की ओर इशारा किया और उसको पास में बुलाया। मुकेश के नाम पर 30 टीन की पर्ची काटने की बात कहकर टीन देने का आदेश दिया। पहला कर्मचारी कार्यालय में जाकर बैठ गया। वह कार्यालय में करीब 15 मिनट तक बैठा रहा। मुकेश की नजर बचते ही वह रफूचक्कर हो गया। उसको आसपास खोजा और अन्य स्टाफ से भी जानकारी जुटाई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इससे मुकेश को अपने साथ ठगी होने का आभास हुआ। एसीपी साहिबाबाद भाष्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

आज ही पकड़े हैं 30 टीन

कर्मचारियों ने मुकेश को बताया कि नगर निगम टीम ने आज ही गाजियाबाद से देशी घी और रिफाइंड के टीन पकड़े हैं। देशी घी व रिफाइंड रखे-रखे खराब हो जाएंगे। जल्द से जल्द उन्हें बेचा जाना है ताकि नुकसान नहीं हो। देशी घी का टीन 6500 रुपये व रिफाइंड टीन 1500 रुपये में बेचा जाने का सौदा तय हुआ। पूरे सौदे के लिए 72 हजार रुपये दिए जाने थे। मिठाई वाले ने ठगों को 60 हजार रुपये दिए, जबकि 12 हजार रुपये पेटीएम से देने थे।

तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गिरी एनएच-9 से नीचे, 3 लोग घायल

इस घटना में चालक समेत कार सवार तीन लोग घायल हो गए। सभी को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में कार की चपेट में आकर एक राहगीर भी घायल हो गया।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र के एनएच 9 पर राठी मिल के पास बुधवार रात एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर नीचे गिर पड़ी। इस घटना में चालक समेत कार सवार तीन लोग घायल हो गए। सभी को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में कार की चपेट में आकर एक राहगीर भी घायल हो गया। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

बगैर रीडिंग लिए बिल भेज रहे मीटर रीडर

गाजियाबाद। मीटर रीडरों की लापरवाही उर्जा निगम के उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। मीटर रीडर बगैर रीडिंग लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिजली का बिल भेज रहे हैं। बुधवार को राजनगर स्थित विद्युत उपकेंद्र में आयोजित विद्युत समाधान शिविर में लोग कुछ इस तरह की समस्या लेकर पहुंचे। गोविंदपुरम निवासी सतीश चंद कौशिक ने बताया कि उनके मोबाइल पर आए बिजली के बिल में खपत 43360 यूनिट दिखाई गई है जबकि मौके पर मीटर में 42413 यूनिट दर्ज है। उनके बिल में लगभग सात हजार रुपये की गड़बड़ी आई है। संजयनगर निवासी रामशकल सिंह ने बताया कि पिछले दो महीने से कोई भी मीटर रीडर उनके घर पर रीडिंग लेने नहीं आया लेकिन मोबाइल पर आए बिल में 307 यूनिट की गड़बड़ी आ रही है।

आरोप है कि मीटर रीडर द्वारा गलत तरीके से उनके पास लगभग चार हजार रुपये का बिल भेज दिया गया है। गोविंदपुरम निवासी हिमांशु ने बिजली के बिल में नाम बदलवाए जाने, बापूधाम निवासी शायरा बानो ने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वाए जाने के संबंध में शिकायत की। इसके अलावा शिविर में खराब मीटर को बदलवाए जाने, नए कनेक्शन दिए जाने, लोड बढ़वाने, नए विद्युत कनेक्शन लिए जाने से संबंधित 13 शिकायतें आई जिनका मौके पर निस्तारण किया गया।

मीटर रीडरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। संबंधित फर्म को इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

– नीरज स्वरूप, मुख्य अभियंता ऊर्जा निगम

राहुल नहीं चाहते कि किसी चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बने : केशव प्रसाद

मोदी सरकार और प्रदेश में यूपी सरकार की ताकत उनके कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यह बात विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है। 2024 में केंद्र में फिर से भाजपा प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएगी। इसका आभास विपक्षियों को हो चुका है।

गाजियाबाद। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं वह नहीं चाहते हैं कि किसी चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बने। बुधवार को घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ में पहुंचे डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के ओबीसी समाज का अपमान किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में यूपी सरकार की ताकत उनके कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यह बात विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है। 2024 में केंद्र में फिर से भाजपा प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएगी। इसका आभास विपक्षियों को हो चुका है। इसलिए भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे अब एक हो रहे हैं।

पहले बिजली आती नहीं थी अब बिजली जाती नहीं है। करीब 14 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुईं हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन के अधिकारियों को समय से मुआवजा देने के लिए कह दिया गया है। महर्षि कश्यप को देश की आत्मा बताते हुए कहा कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम से लिया गया था।

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज वहां के हालात काफी सुधर चुके हैं। विश्व का पर्यटक अब वहां टूर पर जा रहा है। वहां के लोग अब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार भी गाजियाबाद की जनता भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी।

राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि महर्षि कश्यप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पूरा समाज उनके आदर्शों को आत्मसात करता है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। मंच पर सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, विधायक अतुल गर्ग, सुनील शर्मा, डा. मंजू शिवाच, अजीतपाल त्यागी, नंदकिशोर गुर्जर, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश अग्रवाल, सौरभ जायसवाल समेत काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

काव्य पाठ का हुआ आयोजन

महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कवियों ने काव्यपाठ कर लोगों को तालियां बजाने पर विवश कर दिया। हापुड़ से पहुंचे ओज के कवि विकास खड़खड़ी ने अपनी रचना इतिहास के पन्नों पर कहानियां होंगी, वक्त लेगा वजन किरदारों का। तराजू के पलड़ों पर जवानियां होंगी सुनाकर वाहवाही लूटी। अन्य कवियों में वैभव शर्मा, अमित बेनाम मौजूद रहे।

बेहोश हुआ युवक, अस्पताल पहुंचाया

कार्यक्रम में भीड़ बढ़ने के बाद गर्मी अधिक होने पर एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

जीटी रोड पर लगा जाम

कार्यक्रम के समापन के बाद करीब तीन बजे जीटी रोड पर चौधरी मोड़ से मेरठ तिराहे तक लंबा जाम लग गया। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए अचानक किए गए रूट डायवर्जन से वाहन सवारों को दिक्कतें हुईं। करीब एक घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। नेताओं के काफिले को पास कराने के बाद यातायात सामान्य हो सका।

करीबी ने की थी अधेड़ की हत्या, 11 दिन बाद हुई मृतक की शिनाख्त; जंगल में मिला था व्यक्ति का शव

गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र के मटियाला गांव के जंगल में 25 मार्च की रात 50 वर्षीय व्यक्ति की गमछे से गला घोंटकर की गई हत्या के मामले में 11 दिन बाद शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने मृतक की फोटो के साथ जानकारी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की थी। बुधवार को मृतक के मोदीनगर में रहने वाले साले ने वाट्सएप के एक ग्रुप पर फोटो देखकर मुरादनगर के रहने वाले जयवीर पाल के रूम में शिनाख्त की। अंदेशा है कि उनके परिचित ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस को इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस मृतक के कई करीबियों के मोबाइल फोन की सीडीआर (काल डिटेल रिकार्ड) खंगालकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एसीपी मसूरी निमिष पाटिल का कहना है कि मृतक की पहचान मुरादनगर के रेलवे रोड स्थित न्यू डिफेंस कालोनी के रहने वाले जयवीर सिंह पुत्र रामशरण के रूप में हुई है। कार पर लिखे अपशब्द, फिर महिला से की छेड़छाड़; अगवा करने की कोशिश और फायरिंग, इन बदमाशों को नहीं है किसी का डर वह पिछले काफी समय से कारोबार कर रहे थे और इसमें कामयाब न होने के कारण समय-समय पर काम बदल रहे थे। परिवार में पत्नी जयवती व तीन बच्चे हैं।

2023 Mercedes-Benz GLA, GLB को कंपनी ने किया अपडेट, माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ

2023 Mercedes-Benz GLA GLB को वाहन निर्माता कंपनी ने काफी अपडेट कर दिया है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है। दोनों एसयूवी का स्टाइल काफी दमदार है। दोनों एसयूवी में कम्फर्ट सीटें भी मिलती है।

नई दिल्ली। जर्मन की वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने वैश्विक स्तर पर जीएलए और जीएलबी एसयूवी के नए रुप का खुलासा किया है। दोनों एसयूवी का स्टाइल काफी दमदार है। इसके साथ ही इसमें फीचर भी काफी दमदार है। इसके साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कंपनी इस कार को भारतीय बाजार में इस साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है।

एक्सटीरियर

एसयूवी के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें अपडेट किया गया जीएलए और जीएलबी में नए डिजाइन के ग्रिल, बंपर और हेडलैंप सिग्नेचर हैं। दोनों एसयूवी में एक नया रूप का एलईडी हेडलैंप भी मिलता है। जिसके पहिया का कलर इसके एक्सटीरियर के समान दिखता है। एक एएमजी लाइन भी है जिसमें एक आक्रामक बम्पर डिजाइन, फ्लैट बॉटम स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, चारों ओर एएमजी लोगों और बड़े अलॉय व्हील मिलते हैं।

इंटीरियर

इस कार के इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड का लेआउट पहले जैसा ही है। इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ट्विन-10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है और अब इंफोटेनमेंट को वायरलेस कनेक्टिविटी और अपडेट यूआई मिलता है। दोनों एसयूवी में 'कम्फर्ट' सीटें,हाई-बीम असिस्ट और मानक के रूप में एक रिवर्सिंग कैमरा मिलता है। इसके अतिरिक्त, AMG लाइन वेरिएंट में हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

इंजन

दोनों एसयूवी में अब प्लग-इन और माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दोनों मिलता है। माइल्ड-हाइब्रिड इंजन एक बेल्ट-स्टार्टर-जनरेटर के लिए 48V बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। प्लग- इन हाइब्रिड वेरिएंट अब 60 किमी से अधिक की यात्रा करने में सक्षम है और बैटरी का उत्पादन 5hp से 79hp तक बढ़ा दिया गया है, और मर्सिडीज का दावा है कि बैटरी अब 22kW की गति तक चार्ज करने में सक्षम है।

एएमजी की बात करें तो दोनों एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड फोर-सिलेंडर इंजन मिलता है जो 305 बीएचपी की पावर जनरेट करता है।मर्सिडीज का दावा है कि एसयूवी केवल 5.2 सेकेंड में 0-100 की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटा है।

भारत में, GLA और GLB को 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ पेश किया जाता है। पेट्रोल इंजन 7-स्पीड डीसीटी के साथ आता है और डीजल 8-स्पीड डीसीटी के साथ आता है। आपको बता दें, भारतीय बाजार में GLA की कीमत 46.48 लाख रुपये से शुरू होती है और GLB की कीमत 63.80 लाख रुपये (दोनों कीमत एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं।

इनसाइड

इस कार को खरीदने में न करें देरी, 8 दिन चूके तो देना पड़ जाएगा 12 हजार एक्स्ट्रा

कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि अभी केवल Honda Amaze के दामों में वृद्धि हो रही है। कंपनी Amaze को 1 अप्रैल से 12 हजार रुपये मंहगा कर देगी।

नई दिल्ली। देश में 1 अप्रैल से नए उत्सर्जन मानदंडों को लागू किया जा रहा है। ऐसे में सभी वाहन निर्माता कंपनियों को अपने इंजन में बदलाव करना पड़ रहा है। जापानी वाहन निर्माता कंपनी Honda ने घोषणा की है कि वह Amaze को 1 अप्रैल से 12 हजार रुपये मंहगा कर देगी। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं।

Honda Amaze के सभी वेरियंट हो जाएंगे मंहगे

1 अप्रैल से Honda Amaze के सारे वेरियंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि Honda Amaze के अलग-अलग ट्रिम्स के आधार उनकी क्या कीमत रखी जाएगी। इतना साफ है कि कंपनी अपनी शुरुआती लेवल की कॉम्पैक्ट सेडान Honda Amaze को 1 अप्रैल से 12 हजार रुपए तक मंहगा कर देगी।

Honda City भी होगी मंहगी ?

कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड सेल्स) कुणाल बहल ने ये साफ कर दिया है कि कंपनी अभी केवल Honda Amaze के दामों में वृध्दि कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी उनकी मध्यम आकार की सेडान Honda City की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करेगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड सेल्स) कुणाल बहल ने बताया कि हम 1अप्रैल से Amaze के दामों में 12 हजार रुपये तक बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि ये फैसला कड़े उत्सर्जन नियमों के कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर किया गया है।

सभी कंपनी बढ़ा रही हैं दाम

आपको बतादें कि ये काम केवल Honda ने ही नहीं किया है। नए BS6 फेज-2 नियम और कड़े उत्सर्जन मानदंडों के लागू हो जाने के बाद सभी कंपनियां अपने वाहनों की कीमत को बढ़ा रही हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि वह अगले महीने से अपने मॉडल रेंज की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इसी तरह, टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2023 से अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी।

ह्यूंडई की क्रेटा या वेन्यू खरीदना चाहते हैं तो करना पड़ेगा 8 महीनों का इंतजार ! जानिए क्या है वजह

Hyundai Creta डीजल के लिए 32 हफ्ते वहीं पेट्रोल वेरियंट के लिए 24 सप्ताह का वेटिंग पीरियड हो गया है। hyundai Venue का वेटिंग पीरियड Creta के डीजल वेरियंट के बराबर ही है। Grand i20 nios भी 20 सप्ताह के इंतजार के बाद ही मिल पाएगी।

नई दिल्ली। अगर आप हाल में Hyundai की creta या Venue खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी की इन कारों पर 8 महीनों तक का वेटिंग पीरियड हो गया है। क्या है इसकी वजह आइए जानते हैं।

Creta और Venue की खूब है मांग

कंपनी के मुताबिक बीते कुछ दिनों से इन दोनों मॉडलों की डिमांड बढ़ गई है। यही कारण है कि इनकी डिलीवरी की समय सीमा इतनी बढ़ती जा रही है। अगर आप नई क्रेटा या वेन्यू को घर लाने की सोच रहे हैं तो इनके लिए लंबा इंतजार करना होगा। हालांकि ये वेटिंग पीरियड गाड़ियों के विभिन्न वेरियंट के हिसाब से अलग-अलग है।

कितना है इन कारों का Waiting Period

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai Creta डीजल के लिए वेटिंग पीरियड करीब आठ महीने या 32 हफ्ते का है। वहीं इसके पेट्रोल वेरियंट के लिए आपको 24 सप्ताह या लगभग छह महीने का इंतजार करना पड़ सकता है।hyundai Venue का वेटिंग पीरियड Creta के डीजल वेरियंट के बराबर ही है।

कंपनी की अन्य कारों की बात करें तो Grand i20 nios भी 20 सप्ताह के इंतजार के बाद ही मिल पाएगी। वहीं कंपनी की इकलौती 3-Row वाली एसयूवी Hyundai Alcazar भी लंबे वेटिंग पीरियड पर है। इसके पेट्रोल वेरियंट का वेटिंग पीरियड 16 सप्ताह तक का है।

क्या है अन्य विकल्प

बाजार में Hyundai Creta या Hyundai Venue के अलावा अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। आप Hyundai Creta की जगह Maruti Brezza, Kia Seltos और Skoda Kushaq जैसी SUV को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्रेटा के मुकाबले इनका वेटिंग पीरियड कम है।

वहीं Hyndai Venue के समान गाड़ियों की बात करें तो इसमें KIA Sonet, Mahindra Bolero Neo और Tata Nexon जैसे विकल्प शामिल हैं।

भारतीय कार बाजार में Grand i20 nios को Tata Tiago, Maruti Suzuki Swift और Honda Amaze जैसी कारें कम्पीट करती हैं।

ये हैं 1.5 लाख रुपये से सस्ती बाइक्स, फीचर में भी दमदार

नई दिल्ली। अगर आप एक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसका बजट 1.5 लाख रुपये से कम हो तो ये लेख आपके काम का है। हम आपको ऐसी 5 बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतीय बाजार में 1.5 लाख रुपये से कम एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारी इस सूची में TVS Raider से लेकर RE Hunter 350 तक शामिल हैं। आइए, इनके नाम, दाम और विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं।

TVS Raider

भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS की ये बाइक पिछले वर्ष बाजार में पेश की गई थी। कंपनी ने इसे युवाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। टीवीएस इसे भारतीय बाजार में 99,990 रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर बेचती है। ये कीमत हाल ही में लॉन्च की गई TFT स्क्रीन और 'SmartXonnect' टेक्नोलॉजी वाली TVS Raider की है। 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आने वाला इसका 124.8cc सिंगल-सिलेंडर इंजन 7,500 rpm पर 11.2 bhp की शक्ति और 6,000 rpm पर 11.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। TVS Raider कई एडवांस फीचर्स से भी लैस है।

Bajaj Pulsar NS 200

भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj इसे 147,347 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बेचती है। इसमें दिया गया 199.5 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन 24.13 बीएचपी शक्ति प्रदान करता है। कंपनी इसे सभी वेरियंट में डुअल चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) को स्टैंडर्ड रूप से देती है। अगर आप 200 सीसी इंजन में एक अच्छे लुक वाली बाइक की तलाश कर रहे हैं तो Bajaj Pulsar NS 200 आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

TVS Ronin

बीते वर्ष कंपनी ने अपनी इस बाइको को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। TVS Ronin को स्टाइलिश लुक और दमदार इंजन के साथ पेश किया गया है। बाइक में 225.9cc एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है जोकि 7,750 rpm पर 20.2 bhp की शक्ति और 3750 rpm पर 19.93 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है। आप इसे 1.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं।

Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350 भारतीय बाजार में 350 सीसी सेग्मेंट वाली सबसे सस्ती बाइक है। आप कम दामों में ज्यादा शक्तिशाली इंजन वाली बाइक खरदीना चाहते हैं तो Hunter 350 को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें 349 सीसी का इंजन दिया गया है जो 20.2PS की शक्ति और 27Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है। भारत में इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपये से शुरु हो जाती है।

जलाओ दिमाग की बत्ती

पीके खुराना

हास्य की दुनिया के बेताज बादशाह रहे स्वर्गीय जसपाल भट्टी ने अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम उलटा-पुलटा के एक शो में आधुनिक जीवन की विकृति को चित्रित करते हुए बताया था कि आज के बच्चे खेल के नाम पर कंप्यूटर गेम्स या प्ले स्टेशन गेम्स में खोये रहते हैं और इस कारण शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम से उनका नाता टूट गया है जिसके कारण उन्हें छोटी उम्र में ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।

आज हमारा जीवन बहुत व्यस्त है और करिअर की दौड़ में सरपट भागते हुए हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम जीवन में क्या खो रहे हैं। एकल परिवार में कामकाजी दंपत्ति के बच्चे अकेलापन महसूस करने पर टीवी और प्ले स्टेशन में व्यस्त होने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक परेशानियों से जूझ रहा बच्चा एक बार इनका आदी हो जाए तो वह कई स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाता है। किशोर अथवा युवा होते बच्चे भी व्यायाम के बजाय डिस्कोथेक के रेशमी अंधेरों व चौंधियाने वाली रोशनियों में गुम हो रहे हैं'

जनसामान्य में पीजीआई के नाम से प्रसिद्ध चंडीगढ़ स्थित चिकित्सा शिक्षा एवं शोध के स्नातकोत्तर संस्थान 'पोस्टग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑव मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च' से जुड़े तीन अलग-अलग अध्ययनों ने मेरे दिमाग की बत्ती जलाई है और मुझे उम्मीद है कि ये अध्ययन कुछ और लोगों के दिमाग की बत्ती भी जला सकते हैं। हास्य की दुनिया के बेताज बादशाह रहे स्वर्गीय जसपाल भट्टी ने अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम उलटा-पुलटा के एक शो में आधुनिक जीवन की विकृति को चित्रित करते हुए बताया था कि आज के बच्चे खेल के नाम पर कंप्यूटर गेम्स या प्ले स्टेशन गेम्स में खोये रहते हैं और इस कारण शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम से उनका नाता टूट गया है जिसके कारण उन्हें छोटी उम्र में ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आज लगभग हर घर में केबल टेलिविजन सुविधा उपलब्ध है, यानी हर रोज़, चौबीसों घंटे टीवी के किसी न किसी चैनल पर कोई न कोई मनोरंजक अथवा मनपसंद कार्यक्रम आ ही रहा होता है। हर कोई टीवी का दीवाना है। छोटे बच्चे कार्टून कार्यक्रमों में मस्त हो जाते हैं। मां-बाप इसे बड़ी सुविधा मानते हैं क्योंकि कार्टून शो में खोये बच्चे को कुछ भी और कितना भी खिलाना आसान होता है, बच्चा टीवी में व्यस्त हो जाता है और घर से बाहर नहीं जाता, शरारतें नहीं करता, फालतू की ज़िद नहीं करता। संपन्न आधुनिक शहरी घरों में बच्चों के लिए प्ले स्टेशन पोर्टेबल (पीएसपी) भी उपलब्ध हैं और बच्चे इनमें खोये रहते हैं। मां-बाप सोचते हैं कि बच्चा कार्टून ही तो देख रहा है, लेकिन वे उससे होने वाले दिमागी प्रभाव को नहीं समझ पाते। कार्टून शो में सीन बदलने की गति यानि फ्लिकरिंग इतनी तेज़ होती है कि कई बार बच्चे का दिमाग उसे पकड़ नहीं पाता और वह कन्फ्यूज़ हो जाता है। इससे बच्चे को उलटी होने जैसा महसूस हो सकता है।

सीन बदलने के कारण रोशनी की तीव्रता तेजी

से घटती-बढ़ती है, जिसे फ्लैशिंग कहते हैं। इससे भी बच्चों की आंखों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसे फोटोफोबिया कहा जाता है। लगातार कार्टून देखने वाले अथवा प्ले स्टेशन पर खेलने वाले बच्चे अक्सर इसीलिए बाद में थकान महसूस करते हैं और उन्हें मिरगी की शिकायत हो सकती है। सन 2012 में पीजीआई में पीडियाट्रिक मेडिसिन की प्रोफेसर डा. प्रतिभा सिंघी तथा पीजीआई के ही स्कूल ऑव पब्लिक हेल्थ के डा. सोनू गोयल ने शहर के दो दर्जन से अधिक स्कूलों में हुए एक सर्वेक्षण के परिणामों की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चों द्वारा लंबे समय तक कार्टून देखना अथवा प्ले स्टेशन पर खेलना उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। अल्ज़ाइमर एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रस्त व्यक्ति रोज़मर्रा की साधारण चीजों को भी भूलने लगता है, मसलन अलमारी खोलनी हो तो फ्रिज खोलकर खड़े हो जाएं, बात करते समय भूल जाएं कि बातचीत का विषय क्या था, अपनी कोई बात समझाने के लिए किसी विशिष्ट घटना का जिक्र शुरू कर दें और यह भूल जाएं कि उस उदाहरण से समझाना क्या चाहते थे, हाथ में पकड़ी या गोद में पड़ी किसी चीज को इधर-उधर ढूंढ़ें। डिमेंशिया यानी दिमाग के तंतुओं के मरने के कारण होने वाली बीमारी अल्ज़ाइमर से बचने के लिए तथा स्मरण शक्ति के विकास के लिए आयुर्वेद ब्रह्मी बूटी के प्रयोग की सिफारिश करता है। पीजीआई में न्यूरोलाजी विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर व मुखिया डा. सुदेश प्रभाकर के अनुसार चूहों पर किए प्रयोगों से डाक्टरों ने पाया था कि भूलने की बीमारी के इलाज के लिए ब्रह्मी बूटी सचमुच लाभदायक है और उन्होंने भूलने की बीमारी से ग्रस्त मरीजों पर ब्रह्मी बूटी के क्लीनिकल प्रयोग किए। इसके तहत डिमेंशिया से पीड़ित सौ मरीजों का चयन किया गया।

इनमें से 50 को परंपरागत एलोपैथी दवाएं दी गईं और बाकी 50 को ब्रह्मी से बनी दवाएं। फर्क यह है कि ब्रह्मी से बनी दवाओं की गुणवत्ता और पैकिंग आदि का जिम्मा पीजीआई के ही फार्माकोलाजी विभाग को दिया गया, जहां मान्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी ध्यान रखा गया ताकि दवा के परिणाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किए जा सकें। इस परियोजना की देखरेख कर रही टीम में पीजीआई के न्यूरोलाजी विभाग के डाक्टरों के अलावा एक आयुर्वेदाचार्य को भी शामिल किया गया था। परिणामस्वरूप ब्राह्मी बूटी ने अपना असर दिखाया और मरीजों की हालत में काफी सुधार पाया गया। दिल्ली में रह रहीं डा. पूनम नायर ने चंडीगढ़ योग सभा के तत्वावधान में पीजीआई के साथ मिलकर विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को योगासनों से इलाज की पद्धति का अध्ययन किया ही, साथ ही उन्होंने पीजीआई में कार्यरत नर्सों को भी योगासन के माध्यम से अपने कार्य में दक्षता लाने की शिक्षा दी। यह अध्ययन चिंता, तनाव और उदासी से ग्रस्त मरीजों, उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) से ग्रस्त मरीजों और काम के दबाव से ग्रस्त नर्सों पर आधारित था। मरीजों को तीन समूहों में बांटा गया, पहले समूह को परंपरागत एलोपैथिक दवाइयां दी गईं, दूसरे समूह को यौगिक क्रियाओं, योगासनों, यौगिक प्राणायाम और योग मुद्राओं और काउंसलिंग की यौगिक चिकित्सा दी गई और तीसरे समूह को शवासन, प्राणायाम, खुशी और सफलता की स्थिति में स्वयं की कल्पना करने, अपने इष्ट भगवान के ध्यान आदि से यौगिक विश्राम से संबंधित क्रियाएं करवाई गईं। डाक्टरों और नर्सों का जीवन बहुत कठिन होता है और लगातार रोगियों के संपर्क में रहने के कारण उनका अपना स्वास्थ्य हमेशा खतरे में रहता है। काम का दबाव उन्हें चिड़चिड़ा बना देता है और वे तनावग्रस्त हो सकते हैं।

इसीलिए डा. पूनम नायर ने योग क्रियाओं का प्रयोग नर्सों पर भी किया। मरीजों और नर्सों पर यह प्रयोग कुछ वर्ष चला और इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से उत्साहवर्धक रहे। आज हमारा जीवन बहुत व्यस्त है और करिअर की दौड़ में सरपट भागते हुए हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम जीवन में क्या खो रहे हैं। एकल परिवार में कामकाजी दंपत्ति के बच्चे अकेलापन महसूस करने पर टीवी और प्ले स्टेशन में व्यस्त होने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक परेशानियों से जूझ रहा बच्चा एक बार इनका आदी हो जाए तो वह कई स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाता है। किशोर अथवा युवा होते बच्चे भी व्यायाम के बजाय डिस्कोथेक के रेशमी अंधेरों, चौंधियाने वाली रोशनियों और तेज संगीत के शोर में गुम होते हुए सोच ही नहीं पाते कि उनका जीवन किस ओर बढ़ रहा है। पीजीआई के उपरोक्त तीनों अध्ययनों का लब्बोलुबाब यह है कि योग और आयुर्वेद को एलोपैथी के शोध और गुणवत्ता के मानकों से जोड़ दिया जाए तो चिकित्सा विज्ञान विकसित होगा और रोगियों को लाभ होगा। इन अध्ययनों का एक और महत्वपूर्ण सबक यह भी है कि परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएं और एक-दूसरे को भावनात्मक सहयोग दें। परिवार के सदस्यों का साथ और प्यार किसी भी बच्चे के लिए वरदान है जो उसे जीवन की कठिनाइयां झेलने के काबिल बनाता है और नशे और बीमारी की परेशानियों से बचाए रखता है। इस मंत्र की उपेक्षा करना आसान है, पर उससे उत्पन्न होने वाली परेशानियों का सामना करना बहुत मुश्किल है।

संपादक की कलम से

दंगे की नियति यही है?

23 मई, 1987 को पश्चिमी उप्र में मेरठ के मलियाना में भीषण दंगे हुए थे। दंगे क्या, हम उन्हें 'नरसंहार' करार देते हैं, क्योंकि 68 मासूम लोगों की हत्याएं कर दी गई थीं। करीब 106 घरों को जला दिया गया था। नुकसान और मौत का कोई आकलन किया जा सकता है क्या? अब करीब 36 साल बाद अदालत का फैसला आया है, तो सभी ज़िंदा 40 आरोपियों को 'बरी' घोषित कर दिया गया है। यह न्याय है या विडंबना अथवा दंगों की नियति, परिणति यही होती है! यदि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है, तो न जाने कितने और साल बर्बाद होंगे? हम मलियाना अथवा हाशिमपुरा के पुराने दंगों की तुलना पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में भड़की हालिया सांप्रदायिक हिंसा से नहीं करना चाहते। तुलना की भी नहीं जा सकती। बंगाल के हावड़ा, हुगली और बिहार के सासाराम, नालंदा आदि इलाकों में हिंसा और दंगे लगातार 3-4 दिन तक जारी रहे। सुलगन आज भी महसूस की जा सकती है। यह गंभीर चिंता का सबब है।

सवाल भी उठते हैं कि राम नवमी शोभा-यात्रा, हनुमान जयंती और ऐसे ही हिंदूवादी त्योहारों के मौके पर बंगाल, बिहार क्यों दहकने लगते हैं? ऐसे धार्मिक आयोजन तो भारतीय जीवन के महत्त्वपूर्ण आयाम हैं। मुसलमान भी मुहर्रम, ताजिया पर जुलूस निकालते हैं। सभी को संविधान ने यह धार्मिक आज़ादी दी है। उप्र में 20 फीसदी मुसलमान सर्वाधिक आबादी हैं, लेकिन वह लगभग दंगा-मुक्त राज्य बन चुका है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही भारत के नागरिक हैं और दोनों के समान मौलिक अधिकार हैं। फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह सवाल क्यों किया कि क्या राम ने हथियार लाने को कहा था? यह हिंदू भगवान और आस्थाओं का अपमान है।

क्या ममता का यह मानना है कि हिंदू आबादी हथियारबंद थी और उसी ने राम नवमी की शोभा-यात्रा के मौके पर हिंसा भड़काई? यदि केंद्रीय ताकतें बाहर से गुंडे लाईं और दंगे कराए, तो ऐसे दंगाइयों को चिह्नित कर जेल में डालना भी ममता सरकार का दायित्व है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को सड़क पर उतर कर दंगा, हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करना पड़ा। राज्यपाल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा कोई संवैधानिक, आपराधिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कानून-व्यवस्था के कार्यकारी अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। दंगों और उसके बाद की परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री ही कोई निर्णय ले सकता है। पुलिस उसका पालन करने को बाध्य है। सवाल यह भी है कि क्या हिंदू हिंदुओं के साथ ही लड़ते रहे, उन्हें मारते रहे, पथराव और आगजनी कर सार्वजनिक संपत्ति को जलाते रहे? क्या हिंदुओं ने ही मुसलमानों पर बम, बंदूक, पत्थर से हमले किए? क्या ममता ने इसीलिए भगवान राम वाला बयान दिया? चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय और कोलकाता उच्च न्यायालय को रपटें भेजनी हैं, तो इन सवालों के सटीक स्पष्टीकरण देने ही होंगे। उधर बिहार लगातार जलता रहा है। जलता, भस्म होता और लहू-लुहान बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'सुशासन' का ज्वलंत उदाहरण है।

मेरी राय

शिक्षा से खेलती

प्रसन्नता का विषय यह कि विधानसभा में बहस अब गली-कूचे और हैंडपंप से कहीं आगे निकलकर विश्वविद्यालय के स्तर की हो गई है। विधानसभा सत्र में भर्तियों की जांच ने शिमला और मंडी विश्वविद्यालयों के कान पकड़े, तो कहीं अपने औचित्य की जमीन से फिसल रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल कैंपस पर भी बात हुई। अगर माननीयों को लगता है कि विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया के मानदंड दरकिनार करके कुछ लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, तो इन संदर्भों को पूरी तरह खंगालने की जरूरत है। सरकार से छानबीन इसलिए भी आपेक्षित है क्योंकि विश्वविद्यालयों ने खुद को चंद व्यक्तियों के समूहों या विचारधाराओं के चबूतरों के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया है, जबकि शैक्षणिक उपलब्धियों के खालीपन ने हिमाचल की उच्च शिक्षा को गहरी खाई की तरफ धकेलने का भी काम किया है। आरोपों से घिरे विश्वविद्यालय अगर अपने शैक्षणिक परिचय से मोहताज हैं, तो हम किस अस्तित्व की बात करते हैं। विडंबना यह कि जिस तेजी से मंडी विश्वविद्यालय का उदय हुआ, उसी रफ्तार से इसकी आरंभिक परतों में ही दोषारोपण होने लगा है। राजनीति पहले भी विश्वविद्यालयों से खेलती रही है और अब भी ऐसे विषय ढूंढे जा रहे हैं, जिनके आधार पर शैक्षणिक परिसर सत्ता और विपक्ष को मुकाबिल कर रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आशंका प्रकट की है कि जिस तरह जांच के दायरे खड़े किए जा रहे हैं, उनसे मंडी विश्वविद्यालय की नींव को खतरा है। ऐसे में सवाल यह कि डिनोटिफिकेशन की गाज में यह विश्वविद्यालय भी आ जाएगा। हमें नहीं लगता कि इतने बड़े कदम के लिए अभी स्पष्ट साक्ष्य सामने आए हैं, फिर भी शिक्षा में उचित-अनुचित व वांछित-अवांछित का फैसला होना ही चाहिए। हिमाचल में पिछले दो दशकों से शिक्षा के प्रसार में केवल राजनीति के तहखाने देखे गए और यह एक तरह का सदाबहार सियासी चरित्र बन गया कि नेताओं ने अपनी इच्छा की मूछें किसी न किसी स्कूल, कालेज, इंजीनियरिंग-मेडिकल कालेज या अब विश्वविद्यालयों से चस्पां कर दीं। नतीजतन कई अनावश्यक संस्थान तो खुल गए, लेकिन शिक्षा कहीं पिछड़ गई। उदाहरण के लिए जब से तकनीकी विश्वविद्यालय खुला, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और एमबीए के पाठ्यक्रम निरर्थक हो गए। बेशक शिमला और मंडी के बीच विश्वविद्यालयों का विभाजन हो गया, लेकिन समानांतर पाठ्यक्रमों के विभाजन से अंतर यही आया कि शिक्षा की एक भौगोलिक रेखा कायम हो गई। आश्चर्य यह कि जयराम सरकार ने एक नए विश्वविद्यालय की उत्पत्ति करते हुए यह गौर नहीं किया कि चालीस सालों से धर्मशाला में चल रहे शिमला विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र की वरिष्ठता का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस अध्ययन केंद्र ने कई वकील, जज, स्कूल-कालेज व विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षाविद तथा कारपोरेट जगत के लिए प्रतिभाएं पैदा की हैं, लेकिन राजनीति के खेल में इसके अस्तित्व पर कोई बहस नहीं। आश्चर्य यह कि चंद मेडिकल कालेजों के ऊपर भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का सियासी आविष्कार हो जाता है, लेकिन देश के दस टॉप आयुर्वेदिक कालेजों में शुमार पपरोला कालेज के अस्तित्व को सुधारने का अवसर ही नहीं मिलता। पिछले चौदह सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्तित्व ने जितनी राजनीति पैदा की, उसी का असर है कि इस संस्थान ने शिक्षा को लेकर विचार विमर्श करना ही छोड़ दिया, वरना यहां भी आईआईटी मंडी की तरह शोध व शोधार्थियों पर चर्चा होती। सियासत होना बुरी बात नहीं, लेकिन जहां शिक्षा के पर्यावरण, वातावरण व अनुकूलन को दरकिनार करके, संस्थानों के रंग रौगन पर ही चर्चा हो, वहां शिक्षार्थी भी पेंटर ही साबित होंगे। विधानसभा में चर्चा तो इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि हिमाचल से संबंधी शोध में कौन सा विश्वविद्यालय तीसमार खां साबित हो रहा है।

क्या विस्थापितों का दर्द समझेगी सरकार

कविता सिसोदिया

कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि लाभ तो सभी का होता है, पर खोना कुछ लोगों को ही पड़ता है। किसी समय जिला बिलासपुर के पुराने नगर में एक विशाल बाजार और बस्तियां थीं, जहां सैकड़ों परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट के अंतर्गत उस नगर के स्थान पर आज गोविंद सागर झील है। देश ने विकास किया, दीपक के स्थान पर बिजली के बल्बों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश रोशन हुए, पर इस बांध के लिए बिलासपुर के पुराने नगर के निवासियों को अपना बलिदान देकर विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। वे अपने हाट-घराट, खेत-खलिहान व पुराने साथियों को अभी तक नहीं भूल पाए। आज विश्व का प्रत्येक देश तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। अगर कोई देश विकास पथ पर दो कदम पीछे रह गया तो समझो विश्व में पिछड़ गया। इस विकास व उन्नति के लिए व देश को समृद्धशाली बनाने के लिए बेशक हम पृथ्वी से अंधाधुंध छेड़छाड़ कर रहे हैं।

कई बार हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। पर आज का मानव कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। इसलिए यातायात के साधनों में भी द्रुतगति से बदलाव हो रहा है। बड़े-बड़े मैदानी राज्यों में तो फोरलेन या सिक्स लेन सडक़ें बनाना एक आम बात है क्योंकि समतल भूमि होने के कारण वहां यह काम आसानी से हो जाता है। पर पहाड़ी राज्यों में भी फोरलेन का काम जोर-शोर से आरंभ हो चुका है। किरतपुर-मनाली फोरलेन का निर्माण कार्य लगभग अपने अंतिम चरण में है। इसी के साथ मटौर-शिमला व मंडी-पठानकोट आदि फोरलेन निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए प्रक्रिया जारी है। सर्वे करने वाली कई टीमें आ रही हैं। अभी तक तो इसकी जद में आकर बेघर होने वाले लोग निश्चिंत थे, पर जब सर्वे करने वाली एक टीम ने उनके मकानों के हर कमरे की नाप-नपाई आरंभ कर दी तो उस घर में रहने वालों के दिल डूबने से लगे।

एक मध्यमवर्गीय परिवार को अपने सपनों का महल बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। घर जीवन में एक बार ही बनता है जिसे बड़े सुनियोजित ढंग, उमंग, शौक व दिल लगाकर बनाया जाता है। इसको बनाने में कभी-कभी कई वर्ष लग जाते हैं। एक-एक सामग्री बड़े सोच विचार, धन जोडक़र बड़ी दौड़-धूप करके लाई जाती है। गांव में तो मजदूर और मिस्त्री भी बड़े इंतजार के बाद मिल पाते हैं। इसको सजाने में भी समय लगता है। बड़े हर्षोल्लास से गृह प्रवेश किया जाता है। कुछ लोग अभी कुछ साल पहले ही सेवानिवृत्त होकर अपने सपनों के घर में शेष जीवन आराम से व्यतीत करने की मधुर उम्मीद से आते हैं क्योंकि सारी उम्र नौकरी के स्थानांतरण के कारण न जाने कितने स्थान व मकान बदले, तब कहीं जाकर अपने घर में रहने का शुभ अवसर मिला। पर जब उनकी आंखों के सामने उनके सपनों के नीड़ पर बुलडोजर चलाया जाता है तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। बहुत ही मुश्किल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में बसना। कई परिवार तो अपने नौजवान बेटों-बहुओं के साथ रहते हैं जो मिलकर एक अन्य स्थान पर फिर से घर बना सकते हैं, पर कई परिवार ऐसे भी होते हैं जहां केवल एक बुजुर्ग दंपति अपने समाज के साथ मिलकर रह रहे होते हैं। बेटा-बहू शहर में नौकरी करते हैं और वहीं रहना चाहते हैं। वे अपना घर खोकर चिंता में पड़ जाते हैं। छत पर नियमित रूप से आने वाले पंछी ढूंढते हैं कि वह छत कहां खो गई जहां वे बाल-गोपाल संग चहचहाते थे और दाना-पानी लेते थे।

वे क्यारियां जो बड़े यत्न से फूलों से सजाई थी, जिनमें ऑर्गेनिक विभिन्न सब्जियां उगाई थी, उन पर मलवा फिर जाता है। उस गौशाला में अभ्यस्त पालतू पशु नई दिवारों में अपना पहले वाला स्पर्श टटोलते हैं। वे अमरूद, पपीता, आम, नींबू, गलगल आदि के पौधे भी अपनी बलि देते हैं। वह पीपल का पेड़, वह बावड़ी जिससे जल लेकर पीपल, शिवलिंग और वट वृक्ष पर चढ़ाया जाता था, सबकी स्मृतियों की दिल में टीस सी उठती है। वे मोर व अन्य पक्षियों का कलरव, विभिन्न पौधों की खुशबुओं के साथ चरागाहों की पगडंडियों में सुबह की सैर का अमूल्य खजाना कहीं खो जाता है। उच्च आदर्श नारियां तो यह सब छोडक़र अपने मायके में एक रात भी नहीं रहना चाहती। इस तरह की परिस्थितियां कई विस्थापितों की होती हैं। फोरलेन के लिए सिक्स लेन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। पहले यह भी सुनने में आया था कि डबल लेन की दो सडक़ें बनेंगी। एक से आना होगा और एक से जाना। पर अब फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। घुमारवीं से आगे हमीरपुर रोड डबल लेन है और काफी सुविधाजनक है। उससे आगे शिमला की ओर के पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी इलाकों की तरह सडक़ बनाना क्या आसान होगा? सरकारी कर्मचारी घर को नाप कर चले जाते हैं। किसी भी घर में यह नहीं देखते कि अलग-अलग घरों में दरवाजे-खिड़कियों के लिए कीमती लकड़ी का प्रयोग किया गया है या सस्ता सामान लगाया गया है।

> “
> एक मध्यमवर्गीय परिवार को अपने सपनों का महल बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। घर जीवन में एक बार ही बनता है जिसे बड़े सुनियोजित ढंग, उमंग, शौक व दिल लगाकर बनाया जाता है। इसको बनाने में कभी-कभी कई वर्ष लग जाते हैं। एक-एक सामग्री बड़े सोच विचार, धन जोडक़र बड़ी दौड़-धूप करके लाई जाती है। गांव में तो मजदूर और मिस्त्री भी बड़े इंतजार के बाद मिल पाते हैं। इसको सजाने में भी समय लगता है। बड़े हर्षोल्लास से गृह प्रवेश किया जाता है।

फर्श, दीवारें, छत, बिजली-पानी की फिटिंग कितनी सस्ती है या महंगी है। उन पर कितना व्यय किया गया है? वे सभी प्रकार के घरों का मूल्यांकन एक बराबर करके चले जाते हैं और पूछते भी नहीं कि कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जो कि सही प्रक्रिया नहीं है। सरकार को विस्थापितों के बलिदान का दर्द समझ कर उन्हें नए सिरे से बसने में सहायता करनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भूमि और मकान की कीमत वही होनी चाहिए जिस कीमत पर उन्हें मकान के लिए भूमि खरीदनी पड़ेगी या जो कीमत चल रही हो। जिनके पास कुछ खेत बच गए हैं वहां पर घर बनाने के लिए सामान आदि ढोने के लिए सडक़ बना देनी चाहिए। बिजली-पानी की व्यवस्था के लिए भी विस्थापितों को सहयोग देना चाहिए। कई लोगों के तो पीने के पानी के बोरवैल भी उजड़ जाते हैं। क्या ही अच्छा होता सरकार बेघर होने से पहले एक आवासीय कालोनी की व्यवस्था करके उनको पहले बसने में सहायता करती, फिर उनके घर पर बुलडोजर चलाती। फोरलेन विस्थापितों को भी अन्य प्रोजैक्टों की तरह पुनर्वास की सुविधा देनी चाहिए। सुविधा भी समय पर हो। पौंग बांध विस्थापितों की तरह न हो कि वे न जाने कहां बस गए हैं और राजस्थान में मुरब्बे अब दिए जा रहे हैं। देश की जनता की सुविधा और देश के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास तभी सही अर्थों में सफल होंगे जब इस विकास में बलिदान देने वाली जनता भी खुशहाल हो। 'पूछो न दास्तान-ए-गम/उजड़े हैं किस तरह से हम/देशहित के लिए छोड़ा अपना हित/हमारा त्याग भी नहीं है कम।'

चिंतन विचार

खनिज की खातिर खत्म होती खेती

तालझारी, भेरेंडा, पहाड़पुर में रहने वाले आदिवासी राजमहल परियोजना के लिए अपनी कृषि योग्य जमीन नहीं देंगे। इस जमीन पर किसी सूरत में खनन नहीं होगा

खनन के लिए यदि पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जमीनें ली जायेंगी, तो सबसे पहले ग्रामसभा की मंजूरी जरूरी है, अन्यथा यह गैर-कानूनी हो जायेगा। संविधान की पांचवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूची ने आदिवासियों को उन इलाकों की सारी भूमि का मालिक बनाया है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के अनुसार इस इलाके की जमीन को न तो बेचा जा सकता है और न ही इसका हस्तांतरण किया जा सकता है, चाहे वह आदिवासियों की जमीन हो या गैर-आदिवासियों की, लेकिन विकास का मॉडल दूसरे की ज़मीन छीनकर ही बनता है। झारखंड में ढेर सारी कोयला खदानें हैं, लेकिन वे आदिवासियों के लिए अभिशाप हैं। गोड्डा जिला में कोयला निकालने के लिए राजमहल परियोजना के अंतर्गत ईसीएल (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) लगातार कई गांवों को विस्थापित कर रही है। गोड्डा जिला के लालमटिया प्रखंड के कई गांव देखते ही देखते नक्शे से गायब होकर विकास की भेंट चढ़ गए हैं। पहले कुछ गाँवों को लालच देकर और बाद में कई गाँवों को जबरदस्ती, दमन करके विस्थापित किया गया और खदान बनाकर कोयला निकाला गया। बसडीहा, लोहन्डिया, डकैटा सहित कई गाँव आज हैं ही नहीं या फिर थोड़ा बहुत बचे हैं जो कुछ दिनों में खत्म हो जायेंगे। इसी क्रम में तालझारी गाँव भी है जहाँ आदिवासी समुदाय के संथाल जनजाति के लोग बहुसंख्यक हैं। बेहद शांत और पहाड़ी के किनारे बसे इस गाँव में बहुफसली खेती होती है, लेकिन आज यह गाँव अपने अस्तित्व के लिए सरकारी तंत्र से लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि झारखंड के खतियानी लोगों का यह गाँव गैर-कानूनी तरीके से बसा है। सभी के पास जमीनों के दस्तावेज हैं जो कानूनन वैध भी हैं, लेकिन फिर भी इसे जबरदस्ती खनन के नाम पर विस्थापित करने के लिए गोड्डा का जिला प्रशासन हर हथकंडा अख्तियार कर रहा है। पिछले दिनों जब ईसीएल खनन का अपना क्षेत्र बढ़ा रही थी और तलझारी गाँव की सीमा के पास पहुँच गई थी, उसी समय संथाल समुदाय के हजारों आदिवासी अपने परंपरागत हथियारों के साथ वहां पहुँच गए और अपनी जमीनों पर जबरदस्ती खनन का विरोध किया। गाँव वालों का कहना था कि हम 'जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे।' आदिवासी समाज के लोगों का कहना था कि 'हमें मत उजाड़ो, हमारी जमीनें चली जायेंगी तो हम जीते जी मर जायेंगे। यहां खदान से कोई फायदा नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और प्रकृति का नुकसान कर रही है। इसके साथ-साथ आदिवासी संस्कृति और आजीविका भी संकट में है।'

इसके बावजूद प्रशासन ईसीएल के लिए जबरदस्ती जमीन अधिग्रहीत करने की जोर-आजमाइश करता हुआ कंपनी के एजेंट के रूप में दिखा। जब आदिवासी पुरुष थक गए तो आदिवासी महिलाओं ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। इस संघर्ष में महगामा के एसडीओपी सहित सुरक्षा बलों के पांच जवान और लगभग एक दर्जन ग्रामीण घायल हुए तथा एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। संघर्ष, तनाव और ग्रामीणों की नारेबाजी के बीच ईसीएल के अफसरों ने तालझारी गांव में अधिग्रहित जमीन पर बुलडोजर और जेसीबी की मदद से सीमांकन और समतलीकरण शुरू करा दिया। इस क्षेत्र में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ईसीएल ने अपनी राजमहल कोल परियोजना के विस्तार के लिए बीते पांच सालों में बोआरीजार प्रखंड के तालझारी गांव की 125 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। वर्ष 2018 से ही वहां ईसीएल की ओर से खदान विस्तार की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तालझारी के रैयतों सहित आसपास के गांवों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची के अनुसार कोई भी कार्य बिना ग्रामसभा की सहमति के शुरू नहीं किया जा सकता। वर्ष 2018 में तालझारी गाँव के ग्रामीणों ने ग्रामसभा के माध्यम से निश्चय किया था कि गाँव और गाँव की बाकी जमीनों को किसी भी हाल में कोयला खनन के लिए ईसीएल को नहीं दिया जायेगा।

फिर भी जबरदस्ती कई प्रयास किये गए कि जमीन हथिया ली जाए, लेकिन यह नहीं हो सका। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईसीएल प्रबंधन ने पूर्व में लोगों को ठगने का काम किया है जिसका नतीजा है कि पूर्व में हुए विस्थापित लोगों में कइयों को आज तक मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास नहीं मिला है। वहीं रैयतों की जो जमीन ली गयी है, वह ग्रामसभा की सहमति की बजाय कुछ लोगों को प्रबंधन द्वारा अपने पक्ष में करके ली गई है। ऐसे में, बगैर ग्रामसभा के भूमि-अधिग्रहण को वे नहीं मानते। आज से करीब सात-आठ साल पहले गोड्डा में अडानी कंपनी का प्रवेश हुआ था। परसपानी गाँव में पॉवर प्लांट लगना था, वो भी बंजर जमीन पर, लेकिन राजनीति के कारण वहाँ जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया। बाद में मोतिया गाँव के लोगों ने अडानी का स्वागत किया, हालांकि कुछ लोगों द्वारा विरोध भी हुआ।

इनसाइड

भारत दौरे पर रहेंगे अजय बंगा, PM मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण से करेंगे मुलाकात

विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय बंगा आज से दो दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

नई दिल्ली। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका के उम्मीदवार अजय बंगा दो दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। वह 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर समेत कई दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके बीच भारत की विकास प्राथमिकताओं, विश्व बैंक और वैश्विक आर्थिक विकास चुनौतियां पर चर्चाओं होंगी। इसके अलावा, बंगा लर्नेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का भी दौरा करेंगे, जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से स्थापित व्यावसायिक संस्थानों का एक नेटवर्क है, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। बंगा संस्थान के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और कार्यक्रम के प्रतिभागियों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों और निजी क्षेत्र के भागीदारों से मिलेंगे। इस दौरान वह इस पर चर्चा करेंगे कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों, विशेष रूप से युवा लोगों के जीवन और आर्थिक अवसरों में सुधार कैसे कर रहा है। एक बयान में कहा गया है कि बंगा के नामांकन की घोषणा के तुरंत बाद भारत सरकार ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया और तबसे विभिन्न सरकारों के गठबंधन ने बंगा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसमें बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, घाना, इटली, जापान, केन्या, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य और ब्रिटेन शामिल हैं। अपने वैश्विक भ्रमण के दौरान बंगा ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, हितधारकों, व्यापारिक नेताओं, उद्यमियों और नागरिक समाज के साथ मुलाकात की। इसमें कहा गया है कि अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, विकास विशेषज्ञों, अधिकारियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और पूर्व सरकारी अधिकारियों का समर्थन हासिल करते हुए वह अपनी उम्मीदवारी के लिए निरंतर गति बनाए हुए हैं। अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं।

भारत में बैन हो सकते हैं ऑनलाइन बेटिंग एप, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला

नए गेमिंग नियम ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म पर दांव लगाने वाले किसी भी गेम को प्रतिबंधित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नए नियमों की घोषणा की है।

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों को जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नए नियमों की घोषणा की। नए गेमिंग नियम ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म पर दांव लगाने वाले किसी भी गेम को प्रतिबंधित करते हैं। वहीं इन नियमों के अनुसार, सभी ऑनलाइन गेम्स को एक सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (SRO) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

ये हैं नए नियम

सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जुआ लगाने वाले या सट्टेबाजी में शामिल ऑनलाइन गेम नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के दायरे में आएंगे। राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि हम एक ऐसे ढांचे के साथ काम कर रहे हैं जो सभी ऑनलाइन गेमिंग को एक एसआरओ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी एसआरओ निर्धारित करेगा कि गेम में गैम्बलिंग है कि नहीं। उन्होंने कहा कि कई एसआरओ होंगे, और इन एसआरओ में उद्योग समेत सभी हितधारकों की भागीदारी होगी, लेकिन यह उद्योग तक सीमित नहीं है।

सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन करेगा निगरानी

सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हर एक गेम की निगरानी और निर्धारण के लिए सेल्फ- रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। उन्होंने कहा कि अनुमति इस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि क्या एप में दांव लगाना शामिल है। यदि दांव लगाना शामिल है, तो एसआरओ यह कहने की स्थिति में होगा कि उन ऑनलाइन खेलों की अनुमति नहीं है। यानी एप को एसआरओ की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

एक्सेंचर में जाएंगी 19000 नौकरियां, कंपनी ने राजस्व वृद्धि और मुनाफे का अनुमान भी घटाया

माना जा रहा है मंदी से आशंका से परेशान उद्यमों को देखते हुए और प्रौद्योगिकी बजट में कटौती की चिंताओं के बीच कंपनी ने गुरुवार को अपनी वार्षिक राजस्व वृद्धि और लाभ पूर्वानुमानों को भी कम कर दिया है। कंपनी के ताजा अनुमानों के अनुसार स्थानीय मुद्रा में उसकी वार्षिक राजस्व वृद्धि 8% से 10% तक रह सकती है।

नई दिल्ली। आईटी सेवा प्रदाता कंपनी एक्सेंचर ने गुरुवार को कहा कि वह लगभग 19,000 नौकरियों में कटौती करेगी। कंपनी ने अपने वार्षिक राजस्व और मुनाफे के अनुमानों को भी कम करने का फैसला किया है। कंपनी के इस फैसले से ताजा संकेत ये मिल रहे हैं कि बिगड़ते वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण से आईटी सेवाओं पर कॉर्पोरेट कंपनियां अपना खर्च कम करने में जुट गईं हैं।

मंदी की आशंका के बीच कंपनी ने खर्च घटाने पर दिया जोर

माना जा रहा है मंदी से आशंका से परेशान उद्यमों को देखते हुए और प्रौद्योगिकी बजट में कटौती की चिंताओं के बीच कंपनी ने गुरुवार को अपनी वार्षिक राजस्व वृद्धि और लाभ पूर्वानुमानों को भी कम कर दिया है। कंपनी के ताजा अनुमानों के अनुसार स्थानीय मुद्रा में उसकी वार्षिक राजस्व वृद्धि 8% से 10% तक रह सकती है। पहले कंपनी ने 8% से 11% की राजस्व वृद्धि का अनुमाना लगाया था।

शेयर में आया चार प्रतिशत का उछाल

कंपनी ने बताया है कि उसकी ओर से की जा रही छंटनी में आधे से अधिक गैर-बिल योग्य कॉर्पोरेट कर्मचारी प्रभावित होंगे। कंपनी में छंटनी की खबर सार्वजनिक होने के बाद शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में चार प्रतिशत का उछाल दिखा।

मूडीज ने कहा-एशिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की कमजोरी चिंताजनक, भारत पर ज्यादा खतरा

मूडीज ने ये भी कहा कि अगर रुपये की स्थिति मजबूत नहीं होती है तो आरबीआई को मजबूरन बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कमजोर रुपये को और अधिक टूटने से बचाने के लिए दरों में इजाफा करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। मूडीज एनालिटिक्स ने एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। मूडीज का कहना है कि एशिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्राओं में कमजोरी का जोखिम चिंताजनक है। सबसे ज्यादा खतरा भारत पर है। अगर रुपया और अन्य मुद्राएं ऐसे ही कमजोर होती रहीं तो इसका खासा असर तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

मूडीज के अनुसार, रुपये की कमजोरी के चलते एशिया की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। भारतीय रुपया लगभग एक साल से अस्थिर था और प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से कई नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर 2022 में, रुपये ने अपने इतिहास में पहली बार 83 अंक को पार किया। अभी एक डॉलर की कीमत 82 रुपया है।

मूडीज ने ये भी कहा कि अगर रुपये की स्थिति मजबूत नहीं होती है तो आरबीआई को मजबूरन बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कमजोर रुपये को और अधिक टूटने से बचाने के लिए दरों में इजाफा करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में और क्या कहा गया?

मूडीज का कहना है कि आयातित वस्तुओं की उच्च लागत का सामना करने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा जारी मौद्रिक नीति को मजबूत करने से मुद्रा का मूल्यह्रास शुरू हो गया। किसी भी सख्त मौद्रिक नीति के बीच बेहतर और स्थिर रिटर्न के लिए निवेशक अमेरिका जैसे स्थिर बाजारों की ओर रुख कर सकते हैं। आमतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बाजार में तरलता प्रबंधन के माध्यम से हस्तक्षेप करता है, जिसमें रुपये में भारी मूल्यह्रास को रोकने की दृष्टि से डॉलर की बिक्री भी शामिल है।

रिपोर्ट में भारत की मुद्रास्फीति का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि यह अब नहीं बढ़ रही है, लेकिन उच्च खाद्य कीमतें एक प्रमुख चिंता का विषय हैं। बता दें कि फरवरी में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 10 महीनों में लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाने का एलान किया था। इसके चलते लोन की ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी हुई।

आरबीआई ने आठ फरवरी 2023 को मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर को फिर से 0.25 फीसदी बढ़ा दिया था। यह छठी बार था जब केंद्रीय बैंक ने पिछले साल मई से लगातार रेपो दर में वृद्धि की। इसके पहले आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट में 35 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोत्तरी की थी। अब ताजा बढ़ोत्तरी के बाद रेपो रेट बढ़कर 6.5 फीसदी हो गई है। मूडीज का दावा है कि अगर मुद्रा में कमजोरी जारी रही तो अगले महीने यानी अप्रैल में भी आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकती है।

अरबपतियों की संख्या 8 फीसदी घटी, भारत में 16 नए बने, अदाणी की संपत्ति में 60 फीसदी की गिरावट

एम3एम हुरून ग्लोबल अमीरों की सूची के अनुसार, 2023 में पूरी दुनिया में 99 शहरों के 18 उद्योगों से 176 नए अरबपति बने। 2022 में कुल 3,384 अरबपति दुनिया में थे। 2023 में इनकी संख्या घटकर 3,112 रह गई है।

नई दिल्ली। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती से इस साल जहां दुनियाभर के अरबपतियों की संख्या में 8 फीसदी की कमी आई है, वहीं भारत में 16 नए अरबपति बने हैं। इन 16 में शीर्ष पर राकेश झुनझुनवाला का परिवार है। राकेश के निधन के बाद से उनकी पत्नी इस समय कारोबार संभाल रही हैं।

एम3एम हुरून ग्लोबल अमीरों की सूची के अनुसार, 2023 में पूरी दुनिया में 99 शहरों के 18 उद्योगों से 176 नए अरबपति बने। 2022 में कुल 3,384 अरबपति दुनिया में थे। 2023 में इनकी संख्या घटकर 3,112 रह गई है। ये सभी 69 देशों से हैं और ये 2,356 कंपनियों के मालिक हैं। पांच सालों में भारतीय अमीरों की संपत्ति 360 अरब डॉलर बढ़ी जो हांगकांग की जीडीपी के बराबर है।

60 फीसदी घटकर 53 अरब डॉलर रह गई अदाणी की संपत्ति

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन के जेफ बेजोस की संपत्ति में इस साल 70 अरब डॉलर की गिरावट आई है जो मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी को हुए घाटे से भी ज्यादा है। अदाणी की संपत्ति 28 अरब डॉलर घटकर 53 अरब डॉलर रह गई है। इसमें 60 फीसदी की गिरावट आई है। यानी हर हफ्ते 3,000 करोड़ रुपये घटी है। इससे अमीरों की सूची में वे दूसरे स्थान से गिरकर 23वें पर आ गए हैं। अंबानी की संपत्ति 21 अरब डॉलर घटी है।

बेजोस को सबसे ज्यादा नुकसान

नुकसान वाले अरबपतियों में जेफ बेजोस शीर्ष पर हैं और उनकी संपत्ति 118 अरब डॉलर है। जबकि 53 अरब डॉलर की संपत्ति वाले अदाणी छठे और 82 अरब डॉलर वाले अंबानी सातवें स्थान पर हैं।

टेस्ला के एलन मस्क को 48 अरब डॉलर, सर्जी ब्रिन को 44 अरब डॉलर और लैरी पेज को 41 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। डीमार्ट के मालिक आरके दमानी की संपत्ति 30% घटी है। वे शीर्ष 100 अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं।

पिछले साल UPI से हुई 195 करोड़ से अधिक का लेनदेन

95 हजार लोग हुए धोखाधड़ी का शिकार

2020-21 में 77 हजार और 2021-22 में 84 हजार लोग यूपीआई से लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी के शिकार हुए थे

परिवहन विशेष न्यूज

चिंता की बात ये है कि धोखाधड़ी के शिकार होने वालों की संख्या पिछले तीन साल से बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में 77 हजार और 2021-22 में 84 हजार लोग यूपीआई से लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी के शिकार हुए थे।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया है कि वित्तीय वर्षर 2022-23 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए 125 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है। इस दौरान 95 हजार से ज्यादा लोग धोखाधड़ी के शिकार भी हुए हैं। चिंता की बात ये है कि धोखाधड़ी के शिकार होने वालों की संख्या पिछले तीन साल से बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में 77 हजार और 2021-22 में 84 हजार लोग यूपीआई से लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी के शिकार हुए थे।

सरकार ने क्या कहा?

संसद में आंकड़ो को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 125 करोड़ से अधिक का यूपीआई लेनदेन पूरा किया गया था, जो पिछले तीन वर्षों से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी वैश्विक स्वीकृति मिली है। सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस, नेपाल और भूटान जैसे देशों ने भी इसे अपना लिया है।

राज्यसभा सांसद ने उठाया था सवाल

भारत में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सवाल उठाया था। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कराड ने संसद में कहा, 'UPI एप्लिकेशन एक अज्ञात लाभार्थी को भुगतान शुरू करने वाले उपयोगकर्ता की इन-ऐप सूचना प्रदान करते हैं। डिवाइस-बाइंडिंग अवधारणा, जिसमें उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर उसके मोबाइल डिवाइस से जुड़ा होता है, जिससे किसी के लिए हस्तक्षेप करना लगभग असंभव हो जाता है।' कराड ने कहा कि सरकार शिकायतों को दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी लेकर आई है।

अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी खारिज, उमेश पाल हत्याकांड में है आरोपी

अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है।

प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। शाइस्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसका इस घटना से न कोई लेना देना है और न ही कोई मतलब। उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है।

शाइस्ता पर है 25 हजार का इनाम

उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता फरार होने की वजह से 25 हजार रुपये की इनामी हो चुकी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।

शाइस्ता की तलाश में कई जगह दबिश, बढ़ सकता है इनाम

अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शाइस्ता की भी भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस उन पर भी इनाम बढ़ा सकती है। शाइस्ता पर इस समय 25 हजार का इनाम है। उन पर पहले 50 फिर ढाई लाख का इनाम घोषित किया जा सकता है।

सीसीटीवी फुटेज वायरस होने के बाद तलाश हुई तेज

उमेश पाल हत्याकांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही शाइस्ता परवीन लापता हैं। उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से कई हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल कीं। पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है। साबिर के साथ सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई।

पीएम मोदी बोले- भाजपा कार्यकर्ताओं का सेवा भाव हनुमान की तरह, ऐसे सधेगा 2024 का एजेंडा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देश के कोने-कोने तक उसके कार्यकर्ता सेवाभाव में जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज 1.80 लाख शक्ति केंद्र और 8.40 लाख बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है...

नई दिल्ली। छह अप्रैल 1980 को गठित हुई भाजपा आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को लगातार आगे बढ़ते रहने का संकल्प दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सेवा के अपने मूल मंत्र को अपनाते हुए देश की जनता की सेवा में लगातार जुटे रहने की बात कही। भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन के जरिए न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किया, बल्कि इसी के माध्यम से 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के सहारे यह कहा कि उन्हें भक्ति और उदारता का पर्याय माना जाता है, लेकिन जब उन्हें राक्षसों का वध करना होता था, तब वे कठोर भी हो जाते थे। इसके माध्यम से उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात ऐसे अवसर पर कही है जब विपक्षी दल केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका पर लगातार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।

उनका आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक बदले के कारण किया जा रहा है। लेकिन इसी मद में सर्वोच्च न्यायालय में 14 विपक्षी दलों का दावा कमजोर होने से भाजपा को और ज्यादा ताकत मिली है। अब यह माना जा सकता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध और ज्यादा कठोर रुख अपनाएगी और अगले लोकसभा चुनाव में इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए जनता के बीच जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके सेवा भाव को भगवान हनुमान की तरह बताते हुए कहा कि उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वे जनता के बीच जाएं और सेवा भाव के जरिए जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भारत आज अपनी शक्ति का अनुभव कर चुका है और वह लगातार आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देश के कोने-कोने तक उसके कार्यकर्ता सेवाभाव में जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज 1.80 लाख शक्ति केंद्र और 8.40 लाख बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर कोने तक पहुंच चुकी है।

भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति क्या है?

राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडेय ने अमर उजाला से कहा कि भाजपा केवल दो लोकसभा सीटों से आज 303 लोकसभा सीटों तक पहुंचने में सफल रही है, तो इसका श्रेय इसकी नीतियों और इसके सर्वोच्च नेताओं का एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार मेहनत करने में जुटे रहना है। उन्होंने कहा कि आज जब पार्टी के स्थापना दिवस समारोहों की शुरुआत की गई तब जेपी नड्डा ने केवल इसे आदेश के तौर पर नहीं पारित किया, बल्कि स्वयं दिल्ली के एक इलाके में पहुंचकर वॉल राइटिंग कर इस अभियान की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जब वे स्वयं आगे बढ़कर अपने हाथ से कोई काम करने लगते हैं तो इससे भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है और वह दोगुने जोश के साथ मैदान में उतरता है। यही कारण है कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। दूसरे दलों में इसी तरह की भावना की कमी देखी जाती है।

बहुसंख्यकों की भावनाओं की कद्र

सुनील पांडेय ने कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी को यह अनुभव हो रहा था कि पूर्व की सरकारों में उसकी उपेक्षा हो रही है। भाजपा ने जनता की इसी नब्ज को पकड़ा और उसे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ दिया। आज उसका परिणाम सामने है। दूसरे राजनीतिक दल भी उसकी नकल करने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरह सेवा भाव और भ्रष्टाचार को प्रमुखता देने की रणनीति अपनाई है, यह माना जा सकता है कि इन्हीं मुद्दों के सहारे वह

भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे अनिल एंटनी, कांग्रेस नेता बोले- यह गलत फैसला

पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद कांग्रेस के स्टैंड पर अनिल ने सवाल खड़े किए थे। अनिल ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी।

नई दिल्ली। भाजपा के स्थापना दिवस समारोह पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अनिल एंटनी ने कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं। इसके बाद अनिल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की।

अपने बेटे अनिल एंटोनी के भाजपा में शामिल होने पर एके एंटनी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनिल के भाजपा में शामिल होने के फैसले ने मुझे आहत किया है। यह बहुत ही गलत फैसला है। भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, वे व्यवस्थित रूप से विविधता और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रहे हैं। भाजपा सिर्फ एकरूपता में विश्वास रखती है, वे देश के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं।

बता दें कि पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद कांग्रेस के स्टैंड पर अनिल ने सवाल खड़े किए थे। अनिल ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। इसके बाद अनिल एंटनी ने अपने सभी पद छोड़ दिए थे।

डाक्यूमेंट्री देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा: अनिल एंटनी

एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भाजपा का समर्थन करते हुए कहा था कि भारतीय संस्थानों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को रखना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा, 'बीजेपी के साथ बड़े मतभेदों के बावजूद, मुझे लगता है कि वे (भारत में) बीबीसी के विचारों को रखते हैं, एक राज्य प्रायोजित चैनल (कथित भारत) पूर्वाग्रहों के एक लंबे इतिहास के साथ हमारी संप्रभुता को कमजोर कर देंगे'।

दुनिया की कितनी बड़ी पार्टी है भाजपा? जानिए 10 सबसे बड़े राजनीतिक दलों के बारे में

1980 में शुरु हुई भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। इस लिहाज से देश की आबादी के करीब 13% लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मौजूदा समय भाजपा के 11 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं।

नई दिल्ली। आज भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। लोग सवाल करते हैं कि महज 43 साल पहले बनी पार्टी कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई? आइए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के टॉप-10 राजनीतिक दल कौन से हैं? इनमें भाजपा, कांग्रेस और भारत की अन्य पार्टियां किस नंबर पर हैं?

संख्या के आधार पर ये हैं टॉप-10 राजनीतिक दल

1. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) : 1980 में शुरु हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। इस लिहाज से देश की आबादी के करीब 13% लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मौजूदा समय भाजपा के 11 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। वहीं पांच राज्यों में सहयोगी दलों के साथ भाजपा सरकार में है। ऐसा नहीं है कि भाजपा शुरू से सबसे बड़ी पार्टी रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक भाजपा सदस्यों की संख्या करीब छह करोड़ थी। पिछले नौ सालों में 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य बढ़े।

2. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) : 23 जुलाई 1921 को पार्टी की स्थापना चीन में हुई। अब 100 साल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। सीसीपी ने नौ करोड़ से ज्यादा पार्टी सदस्य होने का दावा किया है।

3. डेमोक्रेटिक पार्टी (डीईएम) : आठ जनवरी 1828 में अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। मतलब अब तक इस पार्टी को शुरू हुए 195 साल हो चुके हैं। पार्टी का दावा है कि उनके पास 4.80 करोड़ कार्यकर्ता हैं।

4. रिपब्लिकन पार्टी (आरईपी) : अमेरिका की चर्चित रिपब्लिकन पार्टी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी स्थापना 20 मार्च 1854 को हुई थी। पार्टी के पास अब 3.57 करोड़ कार्यकर्ता हैं।

5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) : भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस के अभी 1.80 करोड़ कार्यकर्ता हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो देश की 1.60% लोग कांग्रेस के सदस्य हैं।

6. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) : पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रहे इमरान खान ने पीटीआई की स्थापना 25 अप्रैल 1996 को की थी। पीटीआई के अभी 1.69 करोड़ सदस्य हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह बल्ला (बैट) है।

7. जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (जेडीपी) : 14 अगस्त 2001 में स्थापित हुई इस पार्टी के 1.10 करोड़ सदस्य हैं। तुर्की की ये सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन इसी पार्टी से हैं। इससे पहले वह प्रधानमंत्री भी थे।

8. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) : भारत की तीसरी पार्टी जो दुनिया की दस सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार है। एआईएडीएमके का गठन 49 साल पहले 17 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसके संस्थापक एमजी रामचंद्रन थे।

9. आम आदमी पार्टी (आप) : 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। महज नौ साल के अंदर इस पार्टी से जुड़ने वालों की संख्या एक करोड़ हो चुकी है। पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। अब दिल्ली और पंजाब में आप की सरकार है।

10. चामा चा मपिनदुजी (चाचाम) : तंजानिया की चामा चा मपिनदुजी दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी पार्टी है। इसके 80 लाख सदस्य हैं। पार्टी की स्थापना पांच फरवरी 1977 को जुलीयूस और एबॉड जुबे ने की थी।

सपा-बसपा का क्या हाल है?

भारत की कई पार्टियों ने अपने सदस्यों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं किया है। इसके चलते उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जा सका। भारत की जिन पार्टियों ने अपने सदस्यों की संख्या नहीं जारी की है, उनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, डीएमके, एआईएमआईएम जैसी बड़ी पार्टियां भी शामिल हैं।

केंद्र ने सीबीआई को ऑक्सफैम की जांच करने को कहा, जानें क्या है मामला?

गृह मंत्रालय की ओर से ऑक्सफैम की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से ऑक्सफैम इंडिया की मुसीबत बढ़ गई है। यह जांच भारत विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए, 2010) के उल्लंघन से जुड़े मामले में की जाएगी।

नई दिल्ली। केंद्र ने सीबीआई को ऑक्सफैम की जांच करने को कहा है। केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी को यह निर्देश फॉरेन फंड्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े आरोपों के मामले में दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से ऑक्सफैम की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से ऑक्सफैम इंडिया की मुसीबत बढ़ गई है। यह जांच भारत विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए, 2010) के उल्लंघन से जुड़े मामले में की जाएगी। ऑक्सफैम इंडिया पर आरोप हैं कि उसने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान हस्तांतरित करना जारी रखा। इस अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण प्रतिबंधित हैं।

बता दें कि ऑक्सफैम इंडिया को रसामाजिकर गतिविधियों के लिए विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए, 2010) के तहत पंजीकृत किया गया था और इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से किए गए आईटी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए एक ईमेल से पता चलता है कि ऑक्सफैम इंडिया एफसीआरए- पंजीकृत अन्य संघों को धन भेजकर एफसीआरए, 2010 के प्रावधान को दरकिनार करने की योजना बना रहा था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि ऑक्सफैम इंडिया अपने लाभ के लिए पैसों को अलग-अलग बैंक अकाउंट में रखने की योजना बना रहा था। वहीं, ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों से भी फंडिंग प्राप्त हो रही थी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023